My Notes
राष्ट्रीय

वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना को मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना को मंजूरी दे दी है। ये योजनाा वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम को आगे बढाने के प्रयासों का एक भाग है। इस स्कीम के तहत बीमा कंपनी एलआईसी 10 वर्ष के लिए 8 फीसदी गारंटेड रिटर्न मुहैया कराएगी।

क्या है

1. वित्त मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा है कि यह स्कीम 10 वर्ष के लिए 8 फीसदी गारंटेड रिटर्न के आधार पर एश्योर्ड पेंशन मुहैया कराएगी।
2. इस स्कीम में मासिक, तिमाही, छमाही या सालाना पेंशन लेने का विकल्प होगा।
3. स्कीम मौजूदा वित्त वर्ष में यह स्कीम लाइफ इन्योंशरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लागू करेगी।
4. यह स्कीम वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने के लिए है। इसके अलावा यह स्कीम 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को अनिश्चित मार्केट कंडीशन की वजह से इंटरेस्ट रेट में गिरावट के खिलाफ भी कवर देगी।
5. सब्सिडी स्कीम के तहत एलआईसी को जो रिटर्न मिलेगा और 8 फीसदी एश्योर्ड रिटर्न के बीच जो अंतर होगा उसकी भरपाई के लिए सरकार सालाना सब्सिडी देगी।
6. सीनियर सिटीजंस स्कीम लॉन्च होने की डेट से अगले एक साल तक सब्सक्राइब कर सकेंगे।

पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण

ओडिशा के बालासोर जिले के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज (आइटीआर) से गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल परीक्षण किया गया। 70 किलोमीटर तक मार करने वाला रॉकेट पिनाका अपने साथ 250 किलोग्राम तक विस्फोटक ढोने की क्षमता रखता है।

क्या है

1. मल्टी बैरल गाइडेड रॉकेट पिनाका का यह दूसरा सफल परीक्षण है।
2. इसका पहला परीक्षण 12 जनवरी को हुआ था। पहले इसकी रेंज 40 किलोमीटर थी जो अब बढ़कर 70 किलोमीटर हो गई है।
3. रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने पिनाका के विकास के लिए सेना और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) को बधाई दी है।

कयामत की घड़ी 30 सेकेंड और बढ़ी

डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी राष्ट्रपति बनना, पर्यावरण परिर्वतन के घातक प्रभाव क चलते प्रतीकात्मक 'कयामत की घड़ी' को तीस सेकेंड और बढ़ा दिया गया है। इसके लिए परमाणु हथियार वाले भारत-पाकिस्तान और दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच के बढ़ते तनाव से उत्पन्न खतरे को भी वजह बताया गया है।

क्या है

1. **वैश्विक संस्था बुलेटिन ऑफ एटामिक साइंटिस्ट्स** ने वर्ष 1947 में डूम्सडे क्लॉक की परिकल्पना की थी। इस घड़ी के लिहाज से पिछले साल 2016 को मानवता के लिए उत्पन्न खतरे को दूर करने में विश्व समुदाय को विफल माना गया है। पूरे साल संपूर्ण मानवता पर परमाणु हथियारों और पर्यावरण परिवर्तन का खतरा मंडराता रहा था।
2. **इस काल्पनिक घड़ी का काउंटडाउन शून्य तक होने को परमाणु विस्फोट से जोड़ा गया है।** ताकि पृथ्वी पर लोग परमाणु हथियारों के खतरे को गंभीरता से समझें।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL) 7509975361, (PATNA) 7463950774, (DIBRUGARH) 7086708270, www.ksgindia.com

3. रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व के 90 फीसद परमाणु हथियार रखने वाले अमेरिका और रूस से लेकर नाटो की सीमा वाले सीरिया से लेकर यूक्रेन तक में अत्याधुनिक परमाणु हथियार हैं। अब इन्हें नियंत्रित करने के लिए बातचीत चल रही है।

क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने ज्यादा क्षमता वाले **स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन** का सफल परीक्षण किया है। रॉकेट **'जीएसएलवी एमके 3'** की लॉंचिंग की दिशा में यह बड़ी उपलब्धि है। इस रॉकेट को इसी तिमाही में लांच किया जाना है।

क्या है

1. **'जीएसएलवी एमके 3'** को अगली पीढ़ी का लांचर माना जा रहा है। इसकी क्षमता **चार टन तक के वजन के साथ सेटेलाइट को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट** में पहुंचाने की है।
2. रॉकेट लांचिंग के दौरान क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल बाद के चरणों में लांचर को अधिकतम वेग से धकेलने के लिए किया जाता है ताकि भारी वजन वाले सेटेलाइट को अंतरिक्ष की मनमाफिक कक्षा में पहुंचाया जा सके।
3. **क्रायोजेनिक अपर स्टेज सी-25 इंजन** का यह परीक्षण तमिलनाडु के महेंद्रगिरि स्थित इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में किया गया। यह परीक्षण 50 सेकेंड का था। इसके बाद 640 सेकेंड का दूसरा परीक्षण किया जाना है।
4. सी-25 इसरो द्वारा बनाया गया सर्वाधिक क्षमता वाला अपर स्टेज इंजन है। इसमें ईधन के रूप में तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है।

इंडिया पोस्ट का पेमेंट बैंक को मंजूरी

डाक विभाग के संगठन इंडिया पोस्ट को पेमेंट बैंक का भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस मिल गया है। इससे वह पेमेंट बैंक का कामकाज शुरू कर सकेगा। डाक विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इंडिया पोस्ट को पेमेंट बैंक का लाइसेंस मिल चुका है। वह अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सेवाएं शुरू करेगा। भारती एयरटेल और पेटीएम के बाद इंडिया पोस्ट तीसरा संगठन है जिसे आरबीआइ ने पेमेंट बैंक शुरू करने का लाइसेंस जारी किया है।

क्या है

1. इस लाइसेंस के तहत इंडिया पोस्ट पेमेंट शुरू कर सकेगा। **पेमेंट बैंक की शर्तों के अनुसार वह आम जमाकर्ताओं और छोटे कारोबारियों से एक लाख रुपये तक का डिपॉजिट स्वीकार कर सकेगा।**
2. नए मॉडल की बैंकिंग में मोबाइल कंपनियों, सुपरमार्केट और अन्य संस्थानों को आम लोगों और छोटे कारोबारियों को बैंकिंग सेवाएं देने के लिए लाइसेंस दिये जा रहे हैं। **ये बैंक सामान्य बैंकों से अलग होगा।** उन्हें सीमित डिपॉजिट लेने, रेमिटेंस यानी मनी ट्रांसफर, इंटरनेट बैंकिंग और कुछ अन्य सेवाएं देने की अनुमति दी गई है।
3. **आरबीआइ ने 2015 में इंडियो पोस्ट समेत 11 कंपनियों और संस्थानों को सैद्धांतिक मंजूरी दी थी।** इसके तहत वे पेमेंट बैंक शुरू कर सकते थे। सैद्धांतिक मंजूरी में ही उन्हें भविष्य में लाइसंस देने का प्रस्ताव किया गया था। हालांकि टेक महिंद्रा, सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज के प्रमोटर दिलीप संघवी के एक कंसोर्टियम, आइडीएफसी, टेलीनोर फाइनेंशियल सर्विसेज और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी ने बाद में पेमेंट बैंक लाने की अपनी योजनाएं त्याग दीं।
4. लाइसेंस पाने वालों में एयरटेल ने 3000 करोड़ रुपये निवेश करके पेमेंट बैंक शुरू किया है। वह ग्राहकों को जमाराशियों पर 7.25 फीसद ब्याज दे रहा है। एयरटेल बैंक के ही किसी अन्य खाते में मुफ्त मनी ट्रांसफर की सुविधा दी जा रही है।
5. चीन की **प्रमुख ई-कामर्स कंपनी अलीबाबा द्वारा वित्तीय समर्थित और विजय शंकर शर्मा की प्रवर्तित कंपनी पेटीएम भी लाइसेंस** पाने के बाद पेमेंट बैंक की सुविधा शुरू करने की तैयारी कर रही है। उसने 400 करोड़ रुपये निवेश किया है।
6. इसके अलावा आदित्य बिड़ला नुवो, फिनो पेटेक, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. और वोडाफोन की एम-पेसा भी पेमेंट बैंक लाने की तैयारी में हैं।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL) 7509975361, (PATNA) 7463950774, (DIBRUGARH) 7086708270, www.ksgindia.com

7. **इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अंतरिम एमडी व सीईओ के तौर पर ए. पी. सिंह को नियुक्त किया गया है।** वह विनिवेश विभाग के संयुक्त सचिव और आधार स्कीम लांच करने वाली टीम के सदस्य रहे हैं।

पूर्वोत्तर राज्यों के प्रथम निवेशक शिखर सम्मेलन

केन्द्रीय वस्त्र मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी पूर्वोत्तर राज्यों के लिए आयोजित प्रथम दो दिवसीय "निवेशक शिखर सम्मेलन" का 29 जनवरी 2017 को शिलांग के राज्य कन्वेंशन केन्द्र में उद्घाटन करेंगी। इस सम्मेलन को आयोजन भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से 29-30 जनवरी 2017 को शिलांग में किया जा रहा है। इस शिखर सम्मलेन को नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ अरविंद पाणिग्रहिया, मेघालय के मुख्यमंत्री श्री मुकुल संगमा, केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं एनईसी के अध्यक्ष डॉ जितेन्द्र सिंह, केन्द्रीय वस्त्र राज्यमंत्री श्री अजय टम्टा, केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री श्री किरण रिजिजू, मिजोरम के उद्योग मंत्री श्री एच रोहलूना और अरूणाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री श्री टैमियो टागा सहित कई गणमान्य लोग संबोधित करेंगे।

क्या है

1. **थीम 'पूर्वोत्तर क्षेत्र में अवसरों की तलाश'** के साथ इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य उत्तर पूर्व क्षेत्र को एक वैश्विक निवेश स्थल के रूप में प्रस्तुत करना है और इस पूर्वोत्तर क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों और उत्तर-पूर्वी राज्यों के संयुक्त प्रयास से संभावनाओं का पता लगाना है ।
2. इस शिखर सम्मेलन में पूर्वोत्तर के सभी राज्य, पूर्वोत्तर क्षेत्र के उद्योगों के प्रमुख और देश भर के कई प्रमुख निवेशक भाग लेंगे। इस पूर्वोत्तर क्षेत्र में वस्त्र निर्माण में अपार संभावनाएं हैं जिससे आने वाले समय में रोजगार के नये अवसर उत्पन्न होने की उम्मीद है।
3. **उत्तर-पूर्व राज्य के वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में लगे उद्योगों के लिए यह एक अद्वितीय अवसर होगा।** निवेश के साथ-साथ नए कौशल और उन्नत उत्पादन तकनीक के प्रयोग के लिए भी यह एक सुनहरा अवसर होगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों द्वारा इस सम्मेलन में कई स्टॉल लगाये जायेंगे और निवेशकों के सामने बनाये सामानों को पेश किया जायेगा। इस शिखर सम्मेलन में पूर्वोत्तर में वस्त्र उद्योग में अवसर, उद्यमिता विकास और स्टार्ट अप, वस्त्र डिजाइन और विपणन द्वारा उत्तर-पूर्व में वस्त्र की पहुंच बढ़ाना, वस्त्र उद्योग के वित्तपोषण की व्यवस्था को आसान बनाना और पूर्वोत्तर क्षेत्र में बुनियादी ढांचे में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
4. इस पूर्वोत्तर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने और निर्माण को मजबूती प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों और निवेशकों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना भी है।
5. **इस शिखर सम्मेलन के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय उद्यमियों, संस्थानों और राज्य सरकारों के बीच समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी किये जायेंगे।** वस्त्र मंत्री की उपस्थिति में 15 से अधिक सहमति पत्रों पर इस शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद है। क्रेता-विक्रेता के बीच मुलाकात और प्रदर्शिनियां भी दोनों दिन आयोजित किया जाएगा।

पृष्ठभूमि

1. **पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेष रूप से वस्त्र और हस्तशिल्प के क्षेत्र में, कुशल कार्य बल** और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कच्चे माल के कारण निवेश की अपार संभावनाएं हैं। वस्त्र मंत्रालय 1050 करोड़ रूपये से अधिक की हथकरघा, हस्तशिल्प, रेशम उत्पादन, परिधान और परिधान उत्पादन, तकनीकि वस्त्र उत्पादन सहित कई परियोजनाओं में पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में भारत सरकार की श्एक्ट ईस्टश नीति के तहत कार्य करते हुए लागू कर रही है।
2. इन परियोजनाओं ने इस इलाके में वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में विनिर्माण कर विकास के लिए एक आधार बनाया है। अन्य मंत्रालयों ने भी इस क्षेत्र में कई योजनाओं को विभिन्न प्रोत्साहन / रियायतें देकर निवेश उपलब्ध कराया है।इस निवेशक शिखर सम्मेलन के जरिए सरकार निवेशक और क्षेत्र की दूरी को पाटने का प्रयास करेगी।
3. इस शिखर सम्मेलन को आयोजित करने के निर्णय की घोषणा केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने 10 नवंबर 2016 को नई दिल्ली में आयोजित वार्षिक सम्मेलन में किया था ।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL) 7509975361, (PATNA) 7463950774, (DIBRUGARH) 7086708270, www.ksgindia.com

'मिशन 41के'

रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु ने भारतीय रेलवे की ऊर्जा संबंधी पहलों पर बाह्य हितधारकों के साथ गोलमेज परिचर्चा के दौरान **'मिशन 41के' के बारे में विस्तृत जानकारी दी।** श्री सुरेश प्रभु ने कहा कि रेल मंत्रालय ने अगले दशक में **रेलवे की ऊर्जा लागत में 41,000 करोड़ रुपये की बचत करने के लिए 'मिशन 41के' तैयार किया है**। उन्होंने ने कहा कि विभिन्ना हितधारकों की भागीदारी के साथ इस व्या पक रणनीति पर अमल के लिए हम नियामकीय रूपरेखाओं से लाभ उठायेंगे और नई प्रौद्योगिकियों पर गौर करेंगे। उन्हों ने कहा कि यह सभी चीजों पर नये सिरे से गौर करने और एक आदर्श आधार-रेखा निर्धारित करने का एक अच्छो अवसर है। रेल मंत्री ने कहा कि पिछले दशक में किये गये **समस्त विद्युतीकरण कार्यों को दोगुना किया जायेगा** और यह **भारतीय रेलवे के ऊर्जा मिश्रण को बदल कर रख देगा। भारतीय रेलवे ने 1000 मेगावाट सौर बिजली और 200 मेगावाट पवन ऊर्जा का लक्ष्या रखा है।**

क्या है

1. भारतीय रेलवे की विभिन्नग पहलों पर हितधारकों के साथ **लगभग 15-16 गोलमेज सम्मेलन** आयोजित करने की तैयारी चल रही है। उन्होंने कहा कि डेटा विश्लेषण पर एक गोलमेज परिचर्चा आयोजित करने की योजना है। भारतीय रेलवे बड़ पैमाने पर डेटा सृजित करती है और इसके पास स्वि उपयोग के लिए विशाल ऑडियंस हैं। इन सभी का इष्टतम इस्तेमाल करने की क्षमता हासिल कर लेने स भारतीय रेलवे के लिए अतिरिक्त राजस्व सृजित करना संभव हो जायेगा।
2. रेलवे ने कहा कि कुल माल ढुलाइ के 45 फीसदी को ढोने का लक्ष्य तभी हासिल किया जा सकता है जब इससे ढ़लाई करना किफायती साबित होगा। इसके परिणामस्वीरूप रेलवे अब सड़क क्षेत्र के साथ प्रतिस्प र्धा करने लगी है।
3. मौजूदा समय में 70 फीसदी ढुलाई बिजली कर्षण (विद्युत ट्रैक्शन) पर होती है। अगले 6-7 वर्षों में 90 फीसदी ढुलाई विद्युत ट्रैक्शन पर करने का लक्ष्यण तय किया गया है। खुली पहुंच के जरिये बिजली की खरीद सुनिश्चित करने से विद्युत खरीद की लागत काफी कम हो गई है, जिसका संचालन व्यय में 25 फीसदी हिस्सा होता है। उन्होंने यह भी कहा कि रेल मंत्रालय ने आवागमन की औसत गति में हर वर्ष 5 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि करने के लिए 'मिशन रफ्तार' शुरू किया है।
4. भारतोय रेलवे का एक अन्य महत्वनपूर्ण मिशन मधेपुरा और मरहौरा में उच्च अश्वशक्ति (एचपी) वाले लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र की स्थापना करना है।
5. रेलवे में अब तक लगभग 50 फीसदी मार्गों को विद्युतीकृत किया जा चुका है, जो ऊर्जा संबंधी बिल को कम रखने और कार्बन के उत्सर्जन को कम करने में बहुमूल्यक योगदान दे रहे हैं। रेल मंत्रालय अपने मिशन विद्यतीकरण के जरिये अगले कुछ वर्षों में विद्युतीकरण को 90 फीसदी के स्तहर पर ले जाना चाहता है, ताकि आयातित ईंधन पर निर्भरता घट सके। ऊर्जा मिश्रण में बदलाव लाना और रेलवे की ऊर्जा लागत को तर्कसंगत करना भी इसके प्रमुख उद्देश्य हैं।

पहली बार 68वां गणतंत्र दिवस पर हुआ

देश के 68वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर विजय चौक से ऐतिहासिक लालकिले तक देश की आन-बान-शान का शानदार नजारा दिखा। इसमें प्राचीन काल से चली आ रही भारत की अनूठी एकता में पिरोई विविधताओं वाली विरासत, आधुनिक युग की विभिन्न क्षेत्रों की उसकी उपलब्धियां और देश की सुरक्षा की गारंटी देने वाली फौज की क्षमता का भव्य प्रदर्शन हुआ। गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि अबु धाबी के शहजादे मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान थे। इस बार गणतंत्र दिवस परेड कई मायनों में खास रही क्योंकि राजपथ पर पहली बार स्वदेशी फाइटर प्लेन तेजस ने उड़ान भरी और 'धनुष' तोप को भी सार्वजनिक किया गया।

इस गणतंत्र दिवस परेड की खास बातें

1. गणतंत्र दिवस के मौके पर पहली बार फ्लाई पास्ट में भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस ने अपना दम दिखाया। इसने बीकानेर के नाल से उड़ान भरा। तेजस 50 हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है।
2. इस साल 68वें गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार एनएसजी कमांडो का दस्ता हिस्सा लिया। इससे पहले एनएसजी कमांडो गणतंत्र दिवस परेड को सुरक्षा-कवच प्रदान करते आए थे। एनएसजी कमांडो ने हाथों में खास एमपी-5 राइफल लिए मार्च निकाला।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL) 7509975361, (PATNA) 7463950774, (DIBRUGARH) 7086708270, www.ksgindia.com

3. पहली बार परेड में संयुक्त अरब अमीरात के 144 जवानों का दस्ता भी सेना के जवानों के साथ परेड की अगुवाई करता नजर आया। मेहमान देश होने के नाते परेड में सबसे पहला दस्ता मेहमान यूएई का रहा।
4. परेड में पहली बार डीआरडीओ की रडार प्रणाली अरुध्र का भी प्रदर्शन भी किया गया। स्वदेशी तकनीक से बना यह भारत का सबसे उन्नत रडार सिस्टम है। इसकी खूबी है कि ये 800 किमी के दायरे में 150 टारगेट का पता लगा सकता है।
5. गणतंत्र दिवस पर पहली बार यूएई के शहजादे मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने हिस्सा लिया।
6. 68वें गणतंत्र दिवस समारोह के मौके पर होने वाले परेड में इस बार 23 झांकियां रहीं। इनमें से 17 राज्यों की और छह मंत्रालय और विभाग की रहीं। 6 साल बाद राजपथ पर दिल्ली को मौका मिला।
7. देसी बोफोर्स कहलाने वाली धनुष तोप भी परेड का हिस्सा लिया। आठ मीटर बैरलवाली ये तोप बोफोर्स से भी ज्यादा यानी, 38 किलोमीटर तक मार कर सकती है।
8. नेशनल हाउसिंग बैंक की झांकी परेड में पहली बार शामिल की गई। इस बार परेड की झांकी में नोटबंदी और डिजीटल पेमेंट के फायदे भी बताए गए। इसी तरह भीम एप और यूपीआई के जरिए कैशलेस ट्रांजैक्शन का मैसेज भी दिया।
9. रिपब्लिक-डे पर कैमिकल अटैक के खतरे को भांपने के लिए छक्त्थ एक स्पेशल यूनिट राजपथ पर तैनात थी। NDRF के एक अफसर ने बताया, 'कैमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर (CBRN) अटैक के खतरे को देखते हुए 90 लोगों की CBRN यूनिट तैनात की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट का अनोखा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग तरह के मामले की सुनवाई करते हुए 16 जनवरी 2017 को 24 हफ्ते को गर्भवती महिला को गर्भपात की इजाजत दे दी। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में मेडिकल टेर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट 1971 को अंसवैधानिक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गयी थी और गर्भपात कराने की इजाजत मांगी थी।

क्या है

1. कानूनन 20 हफ्ते के बाद गर्भपात नहीं कराया जा सकता। इसके तहत सात साल की सजा का प्रावधान है।
2. लेकिन गर्भ में पल रहे भ्रूण में कई तरह की विकृतियां होने और मां की जान के खतरे को देखते हुए कोर्ट की ओर से ऐसा फैसला लिया गया। मुंबई के किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने गर्भ जारी रखने पर महिला की जान को खतरा बताया था।
3. मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट और सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार की सलाह को देखते हुए जस्टिस एस बोबड़े और एल नागेश्वर राव ने गर्भपात की मंजूरी दे दी।
4. कोर्ट ने कहा कि मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट से साफ है कि बच्चे के बचने की उम्मीद नहीं है और महिला की जान को बचाने के लिए गर्भपात किया जा सकता है। हालांकि कोर्ट ने अस्पताल से इस मामले की निगरानी और पूरी प्रक्रिया का रिकार्ड रखने को कहा है।

'शगुन' का शुभारंभ किया

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर न नई दिल्ली में सर्व शिक्षा अभियान के लिए एक समर्पित वेब पोर्टल 'शगुन' का शुभारंभ किया। 'शगुन' का लक्ष्यष प्रमुख योजना 'सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए') की सतत निगरानी के जरिए भारत में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे नवाचारों और प्रगति को दर्शाना है।

क्या है

1. केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने 'दिव्यांमग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा हेतु शिक्षकों को तैयार करने के लिए मास्टर ट्रेनर्स हेतु टूलकिट' का भी अनावरण किया। इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से विश्व बैंक द्वारा तैयार किया गया है।
2. इस अवसर पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने शिक्षा की 'गुणवत्ता' में सुधार के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। उन्होंने कहा कि इस दिशा में मानव संसाधन विकास मंत्रालय सही समझ, गणित, भाषा इत्यादि के संबंध में आवश्यसक क्षमताओं के लिए मूल्यांकन मानक तय करने हतु शिक्षण के परिणामों को संहिताबद्ध करेगा और इस तरह

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL) 7509975361, (PATNA) 7463950774, (DIBRUGARH) 7086708270, www.ksgindia.com

यह सुनिश्चित करेगा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत प्रथम कक्षा से लेकर आठवीं कक्षा तक 'सभी बच्चे कम से कम शिक्षण के न्यूनतम स्तर' को अवश्यत ही हासिल कर लें।

'उड़ान' को उत्साहवर्धक प्रतिक्रियां

क्षेत्रीय संपर्क योजना 'उड़ान' के लिए कार्यान्व यनकारी एजेंसी भारतीय विमानपत्तयन प्राधिकरण (एएआई) को 11 बोलीकर्ताओं से 200 आरसीएस रूटों से संबंधित 45 प्रारंभिक प्रस्ताएव प्राप्त् हुए हैं। प्रारंभिक प्रस्ताईव जमा करने की अंतिम तारीख 16 जनवरी, 2017 को समाप्त हो गई। इन प्रारंभिक प्रस्तासवों में 65 हवाई अड्डे शामिल हैं, जिनमें से योजना के प्रावधानों के अनुसार 52 हवाई अड्डों पर विमानों का संचालन नहीं हो रहा जबकि 13 हवाई अड्डों पर आंशिक रूप से हो रहा है। इन प्रारंभिक प्रस्ताअवों के अब प्रति-बोलियां आमंत्रित की गई हैं जिसे जमा करने की अंतिम तारीख 1 फरवरी, 2017 है। ये रूट या नेटवर्क उन बोलीकर्ताओं को प्रदान किए जाएंगे जो ऐसे रूटों के मुकाबले कम पड़ रही राशि का इंतजाम अर्थात व्याभवहार्यता अंतराल निधियन (वीजीएफ) की निम्नतम आवश्यकता की बोली लगाएंगे। यह सुनिश्चित करने करन के लिए कि बोली प्रक्रिया के संपन्न होने के बाद न्यूरनतम समय-अंतराल के साथ जमीन पर परिचालन आरंभ हो जाए, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा एएआई, राज्यू सरकारों, डीजीसीए एवं नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यू रो के साथ समानांतर कार्रवाई की शुरुआत भी कर दी गई है।

क्या है

1. उल्लखनीय है कि संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने एवं आम लोगों के लिए उड़ान भरना किफायती बनाने के दोहरे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 21 अक्टूबर, 2016 को क्षेत्रीय संपर्क योजना (उड़ान) की शुरूआत की थी।
2. आरसीएस राष्ट्रीनय नागरिक उड्डयन नीति का एक प्रमुख तत्व् था, जिसे मंत्रालय द्वारा 15 जून, 201 को जारी किया गया था। इस योजना, जो 10 वर्षों की अवधि के लिए परिचालन में रहेगी, में वर्तमान हवाई पट्टियों एंव हवाई अड्डों के पुनरोत्था न के जरिए देश के उपयोग न हो रहे एवं आंशिक रूप से उपयोग हो रहे हवाई अड्डों वाले क्षेत्रों को संपर्क प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।
3. इसे केन्द्री य एवं राज्ये सरकारों द्वारा रियायतों एवं ऐसे हवाई अड्डों से परिचालन प्रारंभ करने के इच्छुअक एयरलाइन को व्यरवहार्यता अंतराल निधियन के द्वारा वित्तींय प्रोत्साहन के रूप में अर्जित किया जाएगा, जिससे यात्री विमान किरायों को किफायती रखा जा सके।
4. इस योजना के तहत विभिन्नम दूरियों/समय के रूपों पर समानुपातिक मूल्यत निर्धारण के साथ एक निर्धारित हवाई जहाज पर लगभग 500 किलोमीटर की एक घंटे की यात्रा या एक हैलिकॉप्टकर पर 30 मिनट की यात्रा के किराये की अधिकतम सीमा 2500 रुपये तक सीमित की जाएगी।
5. केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री पी. अशोक गणपति राजू ने इस योजना के तहत प्राप्ती प्रतिक्रियाओं पर संतोष व्येक्तद करते हुए कहा कि यह माननीय प्रधानमंत्रीजी के देश के उपयोग न हो रहे एवं आंशिक रूप से उपयोग हो रहे हवाई अड्डों वाले क्षेत्रों को संपर्क प्रदान करने के विजन को अर्जित करने की दिशा में एक महत्वयपूर्ण कदम है। उन्होंकने कहा कि इस योजना से पर्यटन गतिविधियों एवं सुदूर क्षेत्रों में और श्रेणी-2 एवं श्रेणी-3 के नगरों में रोजगार सृजन को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

जल्लीकट्टू पर विधेयक पारित

तमिलनाडु में जल्लीकट्टू मुद्दे पर फैली हिंसा के बीच सोमवार शाम को राज्य विधानसभा ने अपने विशेष सत्र में इस पर रोक हटाने संबंधी विधेयक पारित कर दिया। इससे पहले इसके स्थायी समाधान की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने खदेड़ दिया। पिछले एक सप्ताह से विरोध प्रदर्शन का केन्द्र बने मरीना बीच समेत राज्यभर में विभिन्न प्रदर्शन स्थलों से सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया गया। मरीना बीच पर मौजूद लोगों ने थाने में आग लगा दी। कुछ जगहों पर पथराव और पुलिस लाठीचार्ज की भी खबरें हैं।

क्या है

1. पुलिस कार्रवाई के बाद राज्यभर में फैली हिंसा के बीच सरकार ने विधानसभा में इसपर स्थायी रोक हटाने संबंधी विधेयक पेश किया। यह विधेयक महज चंद मिनटों में ही सर्वसम्मति से पारित हो गया। इसके साथ ही राज्य में

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL) 7509975361, (PATNA) 7463950774, (DIBRUGARH) 7086708270, www.ksgindia.com

जल्लीकट्टू का आयोजन वैध हो गया है। इससे पहले राज्यपाल विद्यासागर राव ने जल्लीकट्टू से जुड़े अध्यादेश को मंजूरी दी थी। इससे राज्य में जल्लीकट्टू के आयोजन का रास्ता पहले ही साफ हो गया था, लेकिन समर्थक स्थायी समाधान की मांग कर रहे थे। नए कानून के तहत अब इसके आयोजनों की सीसीटीवी रिकॉडिंग होगी।

2. कोयम्बटूर में पुलिस ने वीओसी पार्क ग्राउंड्स से प्रदर्शनकारियों को जबरन हटाया। वरिष्ठ अधिकारियों की अपील नकार देने के बाद बड़ी संख्या में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को उठाकर मैदान से बाहर भेजना शुरू कर दिया। पुलिस को हल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ा।
3. द्रमुक के कार्यवाहक अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने मरीना बीच पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की आलोचना की है। राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता स्टालिन ने एक बयान में कहा, यह निंदनीय है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत करने के बजाय पुलिस बल का इस्तेमाल किया गया। स्टालिन ने इस कार्रवाई को अलोकतांत्रिक करार दिया है।
4. साल 2014 में पेटा की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध लगा दिया था।
5. जल्लीकट्टू को तमिलनाडु में खूब समर्थन मिला. सुपरस्टार रजनीकांत से लेकर ए.आर. रहमान और दक्षिण फिल्मों के कई बड़े कलाकारों ने इसका समर्थन किया।
6. यह तमिलनाडु का एक सांस्कृतिक खेल है, जिसे पोंगल के अवसर पर तीन दिनों तक खेला जाता है। अब यह देखना होगा कि सरकार कैसे इस हालात पर काबू पाती है।

बिहार को मिला ई-गर्वनेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार

बिहार सरकार के कृषि विभाग ने राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल कर राज्य का गौरव बढ़ाया है। यह पुरस्कार उसे ई-गर्वनेंस प्रोग्राम 'ई-एग्रीकल्चर स्कीम मॉनिटरिंग इन्फॉरमेशन सिस्टम के लिए मिला है। कम्प्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रत्येक वर्ष देश के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/सरकारी प्रतिष्ठानों को उनके द्वारा संचालित ई-गर्वनेंस से संबंधित सबसे उत्कृष्ट प्रयासों के लिए पुरस्कृत किया जाता है।

क्या है

1. सोसाइटी को वर्ष 2015-16 के लिए देश भर में संचालित ई-गर्वनेंस प्रयासों के लिए नामांकन में कुल 184 आवेदन मिले थे।
2. कृषि विभाग, बिहार द्वारा संचालित ई-गर्वनेंस प्रोग्राम 'ई-एग्रीकल्चर स्कीम मॉनिटरिंग इन्फॉरमेशन सिस्टम को भी नामांकन के लिए भेजा गया था। प्रत्येक नामांकन के चार चरणों से गुजरने के बाद बिहार के सिस्टम को देश के सबसे उत्कृष्ट ई-गर्वनेंस कार्यक्रम मं एक पाया गया और कोयम्बटूर, तमिलनाडु में आयोजित सोसाइटी के 51वें वार्षिक कन्वेंशन में पुरस्कृत किया गया। पुरस्कार डॉ. अजय कुमार, अपर सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एवं डॉ. अनिर्बान बसु, अध्यक्ष, कम्प्यूटर सोसाइटी ऑफ इण्डिया ने कृषि विभाग, बिहार को दिया।
3. यह पुरस्कार कृषि विभाग की योजनाओं को पारदर्शी तरीके से क्रियान्वयन के दृढ़ निश्चय को दर्शाता है।
4. यह सिस्टम विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं की ऑनलाइन मॉनिटरिंग करने के लिए तैयार किया गया है। इसके माध्यम से राज्य के सभी किसानों का ऑनलाइन पंजीकरण किया जाता है तथा पंजीकरण के उपरान्त किसानों को उपलब्ध कराने वाली यूनिक आईडी द्वारा विभाग में संचालित सभी योजनाओं का लाभ किसान प्राप्त कर सकते हैं।

अंतराष्ट्रीय

25वें एशिया प्रशांत फोरम

फिजी में 16 जनवरी 2017 को 25वें एशिया प्रशांत संसदीय फोरम (एपीपीएफ) का आगाज हो गया। इस फोरम का उद्देश्य शांति एवं सुरक्षा के लिए संसदीय भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करना है। इस पांच दिवसीय फोरम में एशिया प्रशांत क्षेत्र के 20 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लिए हैं जिसमें आस्ट्रेलिया, चीन, जापान, पेरू, फिलीपींस और रूस हैं। फिजी के प्रधानमंत्री वोरेक बेनीमारमा ने संसदीय भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए साझेदारों का आह्वान किया। 2016 में 24वें एपीपीएफ का आयोजन कनाडा में हुआ था।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL) 7509975361, (PATNA) 7463950774, (DIBRUGARH) 7086708270, www.ksgindia.com

मॉरीशस के भारतवंशी पीएम ने बेटे को सौंपी सत्ता

मॉरीशस के भारतीय मूल के प्रधानमंत्री सर अनिरुद्ध जगन्नाथ ने विपक्ष के विरोध के बावजूद बेटे प्रवीण को सत्ता हस्तांतरित कर दी। विपक्ष ने हालांकि उनके इस फैसले को खारिज करते हुए द्वीपीय राष्ट्र में फिर से चुनाव कराने की मांग की है। जगन्नाथ (86) ने राष्ट्रपति अमीन गरीब फाकिम को आधिकारिक रूप से अपना इस्तीफा सौंप दिया है। वह काफी दिनों से इसके संकेत भी दे रहे थे। उनका कार्यकाल 2019 में समाप्त होना था।

क्या है

1. इस्तीफा देने के बाद जगन्नाथ ने कहा, श्प्रधानमंत्री का पद संभालना बड़ी जिम्मेदारी है। यह बड़ा बोझ है। मैंने इसे निभाया, लेकिन अब युवाओं का मार्ग प्रशस्त करने का समय आ गया है।श इसके बाद उनके बेटे प्रवीण (55) को प्रधानमंत्री पद के लिए नामित किए जाने का पत्र सौंपा गया। जिसके पश्चात सोमवार को ही प्रवीण ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की।
2. मॉरीशस हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। मॉरीशस राजनीतिक स्थायित्व का आदर्श नमूना है। लेकिन सत्ता हस्तांतरण इस द्वीपीय देश में अशांति पैदा कर रही है।
3. विपक्ष ने जगन्नाथ के उत्तराधिकारी को अस्वीकार कर दिया है। उसने शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार भी किया। विपक्ष के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री पांल बेरेंगर ने कहा, 'प्रधानमंत्री के लिए सबसे अच्छा होता है कि इस्तीफे से पहले वह नेशनल असेंबली को भंग करते और चुनाव कराते।'
4. स्थानीय रेडियो कार्यक्रमों में बहुत से नागरिकों ने भी ऐसी ही भावनाएं व्यक्त की हैं। उनका कहना है कि उन्होंने जगन्नाथ को वोट दिया था, न कि उनके बेटे को। जगन्नाथ 1982 से कई बार देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं।

चीन को घेरने में भारत कामयाब

हिंद महासागर में चीन की पनडुब्बियों को खोजने में अमेरिका भारत की मदद करेगा। इसको लेकर दोनों देश एक साथ काम करेंगे। यह पहला मौका है जब दोनों देश इस काम को एक साथ अंजाम देंगे। पनडुब्बियों को खोजने में भारत की क्षमता बढ़ाने के मकसद से वाशिंगटन ने बोईंग P-8I सौदे को मंजूरी दे दी है। यह एक मल्टी मिशन मेरिटाइम एयरक्राफ्ट है। इस लिहाज से इसका इस्तेमाल कई जगहों पर किया जा सकता है। इस विमान में लगी अत्याधुनिक तकनीक के बल पर ही इस विमान को सबमैरीन हंटर भी कहा जाता है।

क्या है

1. अमेरिका की पेसफिक कमांड के एडमिरल हैरी हैरिस ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि अमेरिका इस क्षेत्र में भारत की क्षमता को बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि इस दौरान ऑपरेशन की जानकारी को दोनों देश आपस में साझा करेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। इससे ज्यादा उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में दूसरे देशों की पनडुब्बी पर नजर रखना एक बड़ी चुनौती है।
2. जापान-अमेरिका और भारत के बीच अरब सागर मं की गई मालाबार एक्सरसाइज के दौरान भी इसका अभ्यास किया गया था।
3. यह एक्सरसाइज हर वर्ष की जाती है। एडमिरल हैरिस ने कहा कि इसका मकसद अपनी क्षमता को बढ़ाने के साथ-साथ भारत की समुद्री सुरक्षा को और मजबूत करना है।
4. गौरतलब है कि चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर एक आर्थिक कॉरिडोर का निर्माण कर रहा है। इसके जरिए चीन अपने व्यापार को कम लागत पर फारस की खाड़ी तक बेचना चाहता है।
5. हालांकि भारत शुरू से ही इस कॉरिडोर के निर्माण को अवैध बताता आ रहा है। भारत का कहना है कि जिस जगह इस कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है उस हिस्से पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है।
6. वहीं दूसरी ओर चीन ने भारत को भी इस योजना का हिस्सा बनने की अपील की है।

लेजर हथियार से लैस नया मिग-35

रूसी वायुसेना ने चौथी पीढ़ी का अत्याधुनिक मिग-35 लड़ाकू विमान का परीक्षण उड़ान शुरू कर दिया है। यह विमान लेजर गन से युक्त है। मिग-35 1982 के बाद से सेवारत मिग-29 लड़ाकू विमान का सबसे उन्नत संस्करण है। रूस के

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL) 7509975361, (PATNA) 7463950774, (DIBRUGARH) 7086708270, www.ksgindia.com

वायुसेना कमांडर विक्टर बांदरेव ने कहा कि अगले तीन साल में 30 मिग-35 विमान रूसी वायुसेना में शामिल हो जाएंगे। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी मिग-35 का परीक्षण उड़ान देखा। साथ ही पुतिन ने उम्मीद जताई कि इस विमान को रूसी वायुसेना के अलावा दूसरे देश भी खरीदने में दिलचस्पी दिखाएंगे। हालांकि मिग-35 की ये उड़ान इसकी पहली उड़ान के 10 साल बाद हुई है।

क्या है

1. मिकोयान एयरक्राफ्ट कारपोरेशन (मिग) कंपनी द्वारा तैयार मिग-35 में एइएसए रडार होगा जिससे यह दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आएगा। यह एक साथ 10 से 30 निशानों का पता लगाने में सक्षम है। लड़ाकू विमान के दोनों डैनों के आठ खानों में सात टन अत्याधुनिक बम लगाए जा सकते हैं। 2,700 किमी प्रति घंटा की गति से 57,400 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है।
2. मिग-35 जी. एस. 30-1 तोप से युक्त होगा। रूस में बने हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाले हथियार इस पर तैनात किए जा सकते हैं। विमान में दो टर्बो रिएक्टिव इंजन लगे होंगे।
3. इसकी लागत कीमत लगभग 70 अरब (1.1 बिलियन डॉलर) होगी। जो अमेरिकी लड़ाकू विमान एफ-35 की कीमत 68105 करोड़ के मुकाबले आधी है।
4. रूसी उप-प्रधानमंत्री दमित्री रोगोजिन ने कहा, रूस भारत को उन्नत मिकोयान मिग-35 देने की लिए तैयार है। हम जल्द ही भारत सरकार से इस पर बातचीत शुरू करेंगे साथ ही मेक इन इंडिया मुहिम के साथ जुड़कर संयुक्त उद्यम शुरू करेंगे।
5. इससे पहले 2015 में भारतीय वायुसेना ने मिग-35 की जगह फ्रांसीसी विमान राफेल को प्राथमिकता दी थी। भारतीय वायुसेना पुराने पड़ चुके 200 से ज्यादा मिग-21 और मिग-27 विमानों को बदलना चाहती है।

संसद अध्यक्षों के सम्मेलन में शामिल नहीं होगा पाकिस्तान

दक्षिण एशियाई देशों के संसद अध्यक्षों के सम्मेलन में पाकिस्तान भाग नहीं लेगा। सम्मेलन 18-19 फरवरी को इंदौर में होना है। भारतीय संसद और अंतर संसदीय संघ (आईपीयू) ने इसमें शामिल होने के लिए सभी दक्षिण एशियाई देशों को न्योता भेजा था। लेकिन, पाकिस्तान और म्यांमार ने शरीक होने से इन्कार कर दिया है।

क्या है

1. यह सम्मेलन दक्षिण एशियाई देशों के संगठन सार्क से जुड़ा नहीं है। यह आइपीयू की पहल है जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका और अन्य देशों के संसद अध्यक्ष भाग लेंगे। पाक और म्यांमार ने पत्र लिखकर इस सम्मेलन में शामिल होने में असमर्थता जताई है। हालांकि पाकिस्तान ने किस कारण से इन्कार किया है यह साफ नहीं है।
2. सम्मेलन में टिकाऊ विकास लक्ष्यों को हासिल करने पर चर्चा होगी। गौरतलब है कि 2015 में भारत ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा अध्यक्ष को न्योता नहीं दिए जाने पर इस्लामाबाद में हुई कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री यूनियन की बैठक का बहिष्कार किया था।
3. बीते साल की शुरुआत में पठानकोट एयरबेस पर हमले के बाद से दोनों देशों क बीच विदेश सचिव स्तरीय वार्ता रद्द कर दी गई थी।
4. भारत सहित कई देशों के बहिष्कार के कारण इस्लामाबाद में होने वाले सार्क सम्मेलन को भी स्थगित करना पड़ा था। हालांकि बीते दिसंबर में अमृतसर में हुए हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में पाकिस्तान ने शिरकत की थी।

भारत सहित 29 देशों ने पनामा दस्तावेज जांच

भारत और 29 देशों ने पनामा दस्तावेज की जांच से जुड़े तथ्यों पर हुई बैठक में चर्चा की है। इसमें कर चोरी में वित्तीय संस्थानों और सलाहकारों जैसे कर मध्यस्थों की भूमिका की जांच भी शामिल है। साझा खुफिया और गठबंधन के संयुक्त अंतरराष्ट्रीय कार्यबल (जेआईटीएसआईसी) की पेरिस में दो दिवसीय बैठक में 30 देशों के राजस्व अधिकारियों ने कर संधियों और ओईसीडी के तहत कानूनी उपायों पर आधारित अपने-अपने यहां प्रचलित बेहतर गतिविधियों और सूचना को साझा किया।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL) 7509975361, (PATNA) 7463950774, (DIBRUGARH) 7086708270, www.ksgindia.com

क्या है

1. तीस राजस्व विभागों ने पनामा दस्तावेज की जांच से प्राप्त तथ्यों को साझा किया। इसमें कर चोरी में वित्तीय संस्थानों और सलाहकारों जैसे कर मध्यस्थों की भूमिका शामिल है। इस आकार के समूह के भीतर इस तरह की सूचना साक्षा करना अनठा है और कर प्रशासन के बीच बेहतर सहयोग का आधार तय करता है।
2. पनामा के लीक हुए दस्तावेज में भारी मात्रा में सूचनाएं उपलब्ध हैं जो 1.1 करोड़ दस्तावेजों में उपलब्ध है। इस दस्तावेज में 21 देशों की 210000 कंपनियों से जुड़ी सूचनाएं शामिल हैं।
3. इन नामों को इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इनवेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने जारी किया। सूची में 500 भारतीयों के नाम भी हैं जिसमें चर्चित कारोबारी, फिल्मी हस्तियां तथा अन्य शामिल हैं।
4. सरकार ने मामले की जांच के लिए विभिन्न जांच एजेंसियों का एक बहु-एजेंसी समूह बनाया। इसमें आयकर विभाग, रिजर्व बैंक, वित्तीय खुफिया इकाई तथा प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी शामिल हैं।

एशिया पैक्ट से बाहर निकलेगा अमेरिका

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने कहा है कि उनका देश एशिया पैक्ट से अपना हाथ खींच लेगा। ट्रंप प्रशासन ने बताया कि अमेरिकी नौकरियों को बचाने के लिए उनकी व्यापार नीति के तहत पहले कदम के रूप में इस फैसले पर अमल किया जाएगा। इसके तहत 12 देशों के ट्रांस-पैसेफिक पार्टनरशिप (टीपीपी) ट्रेड पैक्ट से देश बाहर आ जाएगा।

क्या है

1. ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह के समापन के तुरंत बाद ही ह्वाइट हाउस ने अपना बयान जारी किया। बयान के मुताबिक, व्यापार समझौते का उल्लंघन करने वाले और प्रक्रिया में अमेरिकी कामगारों को नुकसान पहुंचाने वाले देशों के खिलाफ अमेरिका कठोर कार्रवाई करेगा।
2. ट्रंप एक दूसरे व्यापार समझौते को दोबारा अमल में लाने पर प्रतिबद्ध हैं। यह दूसरा समझौता नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एनएएफटीए) है। यह करार 1994 में अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको के बीच हुआ था।

ईरान ने UN के प्रस्ताव को तोड़ किया मिसाइल का परीक्षण

ईरान ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया जिसने लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी तय की। यह जानकारी अमेरिकी अधिकारियों ने दी। वहीं ईरान के इस परीक्षण के बाद इजराइल ने उस पर प्रतिबंध बढ़ाने की बात कही है। अधिकारियों ने बताया कि यह परीक्षण यहां समनान के करीब से किया गया। उन्होंने बताया कि ईरान द्वारा इस तरह का परीक्षण अंतिम बार गत वर्ष जुलाई 2016 में किया गया था।

क्या है

1. इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान द्वारा फिर से बैलेस्टिक मिसाइल परीक्षण पर चिंता व्यक्त करते हुये कहा कि अगले माह वाशिंगटन दौरे के दौरान वह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ईरान के खिलाफ प्रतिबंध कड़े करने पर विचार करने के लिये कहेंगे ।
2. व्हाइट हाऊस की ओर से नेतन्याहु के अमेरिका दौरे की घोषणा होने के तुरंत बाद ही उन्होंने ट्विटर पर कहा, श्ईरान ने फिर बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। यह साफ तौर पर सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का उल्लंघन है।
3. अमेरिकी अधिकारियों ने भी इस बात की पुष्टि की थी कि ईरान ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है जिसने लगभग 1000 किलोमीटर को दूरी तय की। नेतन्याहू ने कहा, 'मेरी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ होने वाली मुलाकात के दौरान मैं ईरान पर प्रतिबंध के बारे में पुनर्विचार करने का आग्रह करूंगा। ईरान की आक्रमकता का जवाब बिना प्रतिक्रिया दिये ही नहीं दिया जा सकता है।'
4. बता दें कि ओबामा प्रशासन ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण को परमाणु समझौते का उल्लंघन नहीं माना था जबकि ट्रंप ने कहा था कि वह तेहरान के मिसाइल कार्यक्रम पर रोक लगायेंगे।
5. ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाने संबंधी संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के मुताबिक ईरान आठ वर्षों तक परमाणु हथियार को ले जाने वाले मिसाइल का परीक्षण नहीं कर सकता। वहीं ईरान ने कहा है कि यह परीक्षण परमाणु हथियारों को ले जाने वाली मिसाइल का नहीं है।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL) 7509975361, (PATNA) 7463950774, (DIBRUGARH) 7086708270, www.ksgindia.com

आतंक के खिलाफ जंग में भारत का साथ देगा यूएई

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत को पूर्ण समर्थन का भरोसा दिलाया है। अबु धाबी के युवराज शेख मुहम्मद बिन जाएद अल नहयान के आगामी भारत दौरे पर यूएई ने द्विपक्षीय रक्षा एवं सुरक्षा संबंधों को आगे बढ़ाने और रणनीतिक समझौतों पर हस्ताक्षर की उम्मीद जताई है।

क्या है

1. प्रिंस शेख इस साल गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि होंगे। इससे पहले 25 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के युवराज के बीच द्विपक्षीय बातचीत होगी। इस दौरान दोनों देशों के बीच 16 समझौते होने हैं।
2. हम आतंकी समूहों से अपनी रक्षा के भारतीय सरकार के हर प्रयास के साथ हैं।श बन्ना के अनुसार, यूएई भारत में पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकी हमले की निंदा करने वाले शुरुआती देशों में था। साथ ही यूएई ने भारत की ओर से हुई सर्जिकल स्ट्राइक का भी समर्थन किया था।
3. उल्लेखनीय है कि 2015 में मोदी के यूएई दौरे पर दोनों देशों के बीच कई समझौते हुए थे। उस वक्त दोनों देशों ने नकदी की आवाजाही को नियंत्रित करने, नियमबद्ध करने और जानकारियों को साझा करने पर सहमति जताई थी। इसे आतंकियों के खिलाफ महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा था।
4. अधिकारियों ने इस समझौते को दाऊद इब्राहिम जैसे वांछित अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की दिशा में अहम कदम बताया था। खबरों में कहा गया था कि यूएई सरकार ने 1993 के मुंबई बम विस्फोट के आरोपी दाऊद की 15 हजार करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है। हालांकि बन्ना ने इस पर कोई टिप्पणी करने से इन्कार कर दिया।

पाक ने अबाबील का पहला परीक्षण किया

पाकिस्तान ने 2200 किलोमीटर की दूरी तक जमीन से जमीन तक मार करने वाली और परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अबाबील का पहला परीक्षण सफलतापूर्वक किया। पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन्स (आईएसपीआर) ने एक बयान में बताया कि अबाबील 2200 किलोमीटर की अधिकतम दूरी तक मार करने और मल्टिपल इंडिपेंडेंट री-एंटरी व्हेकिल (एमआईआरवी) प्रौद्योगिकी का उपयोग कर एक साथ अनेक आयुध ले जाने में सक्षम है।

क्या है

1. यह परीक्षण आयुध प्रणाली के विभिन्न डिजाइन और तकनीकी पहलुओं के मान्यकरण के लिए किया गया था।
2. आईएसपीआर ने कहा कि अबाबील परमाणु आयुधों को ले जाने में सक्षम है और इसकी क्षमता उच्च सटीकता के साथ दुश्मन के रेडारों को मात देते हुए एक साथ अनेक लक्ष्यों को भेदने की है।
3. भारत की तरफ परोक्ष इशारा करते हुए कहा गया कि अबाबील आयुध प्रणाली का विकास बढ़ती क्षेत्रीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा (बीएमडी) माहौल में पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइलों के टिकने की क्षमता सुनिश्चित करने पर लक्षित है।
4. पिछले साल नौ दिसंबर को पनडुब्बी से क्रुज मिसाइल बाबर-3 के सफल परीक्षण के बाद अबाबील परीक्षण किया गया है।

यूएई के साथ तक 14 समझौतों पर लगी मुहर

खाडो के देशों के साथ अपने द्विपक्षीय रिश्तों को नए सिरे से लिखने में जुटी भारत सरकार की कोशिशों का असर दिखने लगा है। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के क्राउन प्रिंस की अगुवाई में यूएई और भारत के बीच जो समझौते हुए हैं उससे साफ है कि अब दोनों देश रणनोतिक व आर्थिक दृष्टिकोण से एक मजबूत साझेदार बनेंगे। अबु धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान इस बार गणतंत्र दिवस पर देश के राजकीय मेहमान हैं। उनके और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद 14 समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये। इसमें रक्षा, सुरक्षा से लेकर व्यापार और सामुद्रिक क्षेत्र तक शामिल हैं। माना जाता है कि यूएई की सरकार ने इस तरह का समझौता बहुत ही कम देशों के साथ किया है।

क्या है

1. वैसे द्विपक्षीय शिखर वार्ता के बाद जो समझौते किये गये हैं उनमें यूएई की तरफ से भारत में किये जाने वाले 75 अरब डालर के निवेश से संबंधित कोई समझौता नहीं है। इस बारे में सहमति मोदी की यूएई यात्रा के दौरान बनी थी। विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने एक दिन पहले ही कहा था कि इस बार निवेश समझौता हो जाएगा।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL) 7509975361, (PATNA) 7463950774, (DIBRUGARH) 7086708270, www.ksgindia.com

2. लेकिन विदेश मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि यूएई अपने वादे के मुताबिक 75 अरब डॉलर भारत के ढांचागत क्षेत्र में लगाने को तैयार है लेकिन अभी तक उन परियोजनाओं का फैसला नहीं हो सका है जहां यह निवेश होगा। इस बारे में दोनों पक्षों के बीच बातचीत चल रही है। वैसे यूएई अभी भी भारत में निवेश करने वाला 10वां सबसे बड़ा राष्ट्र है।
3. बैठक के बाद साझा बयान जारी करते हुए मोदी ने कहा कि, हमने दोनों देशों के बीच के रणनीतिक रिश्ते को ज्यादा उद्देश्यपूर्ण बनाने और कार्यान्वयन आधारित बनाने के लिए एक रोडमैप तैयार किया है। अभी जो समझौते किये जा रहे हैं वे इस रोडमैप पर आगे कदम बढ़ाने में मदद करेंगे। रक्षा व सुरक्षा क्षेत्र में सहयोग स्थापित होने के बाद द्विपक्षीय रिश्ते में और विस्तार हो गया है।
4. उन्होंने कहा कि ये समझौते सिर्फ इन दोनों देशों के लिए नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें रक्षा उपकरणों के निमार्ण के लिए किया गया समझौता भी शामिल है। इससे भारत को अपने रक्षा उपकरणों के लिए एक अहम बाजार भी मिलेगा तो साथ ही अपनी सुरक्षा को नई धार देने में जुटे यूएई को पड़ोस से ही विश्वस्तरीय रक्षा उपकरण मिलने का रास्ता साफ होगा।
5. क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद ने भारत के साथ यूएई के रिश्ते को खास बताते हुए कहा कि दोनों देश एशिया और मध्य पूर्व के इलाके में शांति लाने के लिए काम करेंगे। उन्होंने भारत की तरफ से खाड़ी के देशों के साथ गहरे रिश्ते बनाने की नई कोशिशों की खास तौर पर तारीफ की।
6. मोदी और शेख मोहम्मद के बीच एक घंटे तक व्यक्तिगत वार्ता भी हुई जो बताता है कि दोनों के बीच एक व्यक्तिगत तालमेल बन रहा है।
7. दोनों नेताओं के बीच आतंकवाद और धार्मिक कट्टरता रोकने में एक दूसरे की मदद करने पर भी बात हुई है। सनद रहे कि यूएई अपने आस पास के देशों में हक्कानी नेटवर्क, आइएसआइएस जैसे आतंकी संगठनों के बढ़ते प्रभाव से काफी चिंतित है। यह एक अहम वजह है कि वह भारत के करीब आने की कोशिश कर रहा है।

आर्थिक

आर्थिक सर्वे 2017

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में इकनॉमिक सर्वे पेश किया। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि अगले वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की किसी अन्य अर्थव्यवस्था के मुकाबले तेजी से वृद्धि करेगी।

सर्वे की प्रमुख बातें

1. आर्थिक सर्वेक्षण में वित्त वर्ष 2017-18 के लिए 6.75% से 7.5% की दर से आर्थिक वृद्धि का अनुमान जताया गया है। वैश्विक स्तर पर मांग में उछाल से वित्त वर्ष 2017-18 में तेज आर्थिक वृद्धि होगी। नोटबंदी का वृद्धि दर पर 0.25 से 0. 50 प्रतिशत का असर होगा, लेकिन दीर्घावधि में इससे लाभ होगा।
2. जीएसटी तथा अन्य बुनियादी सुधारों से वृद्धि दर 8 से 10 प्रतिशत पर पहुंचेगी। जीएसटी से वित्तीय लाभ मिलने में समय लगेगा।
3. मौजूदा वित्त वर्ष 2016-17 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर घटकर 6.5 प्रतिशत पर आएगी। पिछले वित्त वर्ष में यह 7.6 प्रतिशत रही थी। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर मौजूदा वित्त वर्ष में महंगाई औसतन 5 प्रतिशत पर ठहरी हुई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना तथा कच्चे तेल की निचली कीमतों से राजकोषीय मोर्चे पर अप्रत्याशित लाभ होगा।
4. सर्वे में आर्थिक गतिशीलता और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की वकालत की गई है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम (यूबीआई) डेटा पर गंभीरता से विचार की जरूरत बताई गई है। सब्सिडी खत्म करने के विकल्प के तौर पर यूबीआई को पेश किया जा सकता है।
5. आर्थिक सर्वे में अर्थव्यवस्था के विकास की राह में तीन बड़े खतरों का जिक्र किया गया है। नोटबंदी से कृषि क्षेत्र पर कैश की कमी का असर दिखेगा। क्रूड कीमतों में उछाल जीडीपी के लिए बड़ा खतरा। वित्त वर्ष 2017-18 में क्रूड में गिरावट का फायदा मिलना बंद हो जाएगा। क्रूड के दाम में उछाल की वजह से रिजर्व बैंक से रेट कट की उम्मीद खत्म हो गई।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL) 7509975361, (PATNA) 7463950774, (DIBRUGARH) 7086708270, www.ksgindia.com

6. व्यक्तिगत आयकर की दरों, जमीन जायदाद पर स्टाम्प (पंजीकरण) शुल्क में कटौती की सिफारिश। ऊंची आमदनी वाले सभी व्यक्तियों को धीरे-धीरे आयकर दायरे में लाकर आयकर का दायरा बढ़ाने का सुझाव। कॉर्पोरेट कर की दरों में कटौती की रफ्तार तेज हो। मनमर्जी पर रोक तथा जवाबदेही बढ़ाने के लिए टैक्स ऐडमिनिस्ट्रेशन में सुधार किया जाएगा। नए नोटों की आपूर्ति बढ़ने से वृद्धि दर सामान्य होगी।
7. इकनॉमिक सर्वे में तीन सेक्टर्स फर्टिलाइजर, सिविल एविएशन, बैंकिंग के निजीकरण की जरूरत बताई गई। सरकार ने सिफारिश मानी तो कृभको, एयर इंडिया, पवन हंस जैसी कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन हो सकता है।
8. वित्त वर्ष 2016-17 में सेवा क्षेत्र में 8.9%, औद्योगिक क्षेत्र में 5.2% की दर से वृद्धि का अनुमान जताया गया है। पिछले वित्त वर्ष में इंडस्ट्री सेक्टर ने 7.4% की दर से वृद्धि दर्ज की थी। मौजूदा वित्त वर्ष में कृषि क्षेत्र के 4.1 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है। पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले यह 1.2 प्रतिशत ज्यादा है।
9. इकनॉमिक सर्वे में श्रम और कर नीतियों में बदलाव की सिफारिश की गई है ताकि परिधान और चमड़ा क्षेत्र को बढ़ावा मिले और ये दोनों विश्व स्तर पर प्रतिस्पधा के लायक बन सकें।
10. सर्वे में सेंट्रलाइज्ड पब्लिकर सेक्टर ऐसेट रीअबिलिटेशन एजेंसी की स्थापना की सिफारिश की गई है।

लघु बचत से एफसीआई को ऋण मंजूर

राष्ट्रीय लघु बचत निधि से भारतीय खाद्य निगम को सस्ता ऋण मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इससे जहां खाद्य सब्सिडी की बचत होगी वहीं सरकार को अपनी बकायेदारी चुकता करने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने राज्यों को लघु बचत निधि से ऋण लेने की बाध्यता से भी मुक्त कर दिया है। राज्य अपनी जरूरतों के लिए खुले बाजार से इससे सस्ती दर पर धनराशि प्राप्त कर सकते हैं।

क्या है

1. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में एफसीआई के लिए एकमुश्त 45 हजार करोड़ रुपये का ऋण मंजूर कर लिया गया, जिसे वह राष्ट्रीय लघु बचत निधि से प्राप्त कर सकता है।
2. भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) फिलहाल बैंकों से अल्पकालिक ऋण 10 फीसद से भी अधिक ब्याज दर पर प्राप्त करता है। जबकि लघु बचत निधि की मौजूदा ब्याज दर किसी भी हाल में वार्षिक 8.8 फीसद से अधिक नहीं है। सरकार के इस प्रावधान से केंद्र पर खाद्य सब्सिडी के बोझ में कमी आएगी।
3. वित्त मंत्रालय के इस प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। एफसीआई अपने इस ऋण का भुगतान प्रति वर्ष नौ हजार करोड़ की किश्तों में कर सकता है, जिसकी शुरुआत वित्त वर्ष 2017-18 में होगी। दरअसल, एफसीआई बैंकों के समूह से अधिक ब्याज दर पर जो ऋण लेता था, उससे उस पर सालाना 8500 करोड़ रुपये का ब्याज का बोझ पड़ता था। लेकिन सरकार के इस नये फैसले से उसे सालाना लगभग पांच हजार करोड़ रुपये की सीधी बचत होने का अनुमान है।
4. केंद्रीय मंत्रिमंडल के इस फैसले से केंद्र व राज्य सरकार के साथ एफसीआई को भी फायदा मिलेगा। लघु बचत की विभिन्न स्कीमों में सरकार सात से 8.5 फीसद तक का ब्याज देती है। लघु बचत निधि से दिये जाने वाले कर्ज के ब्याज की दर वित्त मंत्रालय करता है।

1 जुलाई से लागू होगा जीएएसटी

केंद्र सरकार प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लागू करने की तिथि बदल दी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ऐलान किया कि अब जीएसटी को 1 अप्रैल से नहीं बल्कि 1 जुलाई से लागू किया जाएगा। 1 अप्रैल की तिथि पर सहमति नहीं बनने की वजह से सरकार को जीएसटी लागू करने के लिए और अधिक समय देना पड़ा है।

क्या है

1. जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जीएसटी को लेकर अहम घोषणाएं की। जीएसटी में एक बड़ा पेच केंद्र और राज्यों के बीच टैक्सेशन सिस्टम में ड्यूल कंट्रोल को लेकर था। अरुण जेटली ने कहा कि ड्यूल कंट्रोल को लेकर पूरे दिन चर्चा चली।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL) 7509975361, (PATNA) 7463950774, (DIBRUGARH) 7086708270, www.ksgindia.com

2. वित्त मंत्री ने फिर एक बार स्पष्ट किया कि पूरा टैक्सेशन बेस केंद्र और राज्यों के बीच साझा किया जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया कि 1.5 करोड़ या उससे कम के टर्नओवर वाले 90 फीसदी जीएसटी करदाताओं का आकलन राज्य जबकि 10 फीसदी का केंद्र करेगा।
3. 1.5 करोड़ से अधिक के टर्नओवर वाले जीएसटी करदातओं के आकलन में केंद्र और राज्यों का अनुपात 50:50 फीसदी का होगा। अरुण जेटली ने बताया कि 12 नॉटिकल मील की समुद्री सीमा पर होने वाली आर्थिक गतिविधियों के आकलन का अधिकार राज्यों के पास ही होगा।
4. जीएसटी परिषद की अगली बैठक 18 फरवरी को होगी। उन्होंने इतनी लंबी अवधि के बाद बैठक रखने के पीछे की मुख्य वजह केंद्रीय और राज्यों के वित्त मंत्रियों के आने वाले बजट की प्रक्रिया में व्यस्त होने को बताया।
5. गौरतलब है कि जीएसटी के रूप में बिक्री पर पूरे देश में हर जगह एक ही प्रकार का कर लागू होने से भारत दुनिया का सबसे बड़ा साझा बाजार बन कर उभरेगा। भारत दुनिया की सातवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जीएसटी से कारोबार करने वालों को आसानी होगी। इससे टैक्स चोरी रोकने में मदद मिलेगी और सरकारों का राजस्व बढ़ेगा।

पांच बीमा कंपनियों के शेयरों की सार्वजनिक बिक्री को मंजूरी

सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की पांच साधारण बीमा कंपनियों के शेयरों की सार्वजनिक बिक्री कर उन्हें शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे इन कंपनियों को पूंजी बाजार से धन जुटाने को प्रोत्साहित किया जा सकेगा, साथ ही उनके कामकाज के संचालन में भो सुधार होगा। सरकार ने 2016-17 के बजट में इस योजना की घोषणा की थी।

क्या है

1. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) की बैठक में इस प्रस्ताव को सैद्धान्तिक मंजूरी दी गई। बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया, यह नए शेयर जारी कर या बिक्री पेशकश के जरिये होगा। दोनों विकल्प उपलब्ध होंगे। हम शेयरधारिता का विस्तार करेंगे जिससे सरकार की हिस्सेदारी घटकर 75 प्रतिशत पर आ जाए।
2. मंत्रिमंडल ने नए शेयर जारी कर या बिक्री पेशकश (ओएफएस) के जरिये सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों की सूचीबद्धता के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जेटली ने कहा कि इन कंपनियों में सरकार की हिस्सेदारी धीरे-धीरे घटकर 100 से 75 प्रतिशत पर आ जाएगी।
3. जिन पांच साधारण बीमा कंपनियों को सूचीबद्ध किया जाएगा। उनमें न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनो लि, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि, ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लि, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि तथा पुर्नबीमा कंपनी जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया (जीआईसी) शामिल हैं।
4. सभी प्रक्रियागत औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। अब कंपनियों को शेयर बाजारों तथा सेबी के साथ सूचीबद्धता अनिवार्यताओं को पूरा करना होगा।
5. सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों में सार्वजनिक हिस्सेदारी से उच्च स्तर की पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित हो सकेगी। सरकार ने विदेशी बीमा कंपनियों को संयुक्त उद्यमों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने की अनुमति दी है। इससे पहले सिर्फ 26 प्रतिशत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति थी।
6. देश में कुल 52 बीमा कंपनियां परिचालन कर रही हैं। इनमें से 24 जीवन बीमा क्षेत्र में तथा 28 साधारण बीमा क्षेत्र में हैं।

एफआरबीएम कानून में बदलाव करेगी सरकार

सरकार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन कानून में बदलाव करने की तैयारी कर रही है। एफआरबीएम कानून पर विचार कर रही एन के सिंह समिति ने अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्री अरुण जेटली को सौंप दी है। माना जा रहा है कि सरकार आम बजट 2017-18 समिति की सिफारिशों पर अमल करते हुए बजट सत्र में ही एफआरबीएम कानून में संशोधन के लिए विधेयक पेश कर सकती है। हालांकि समिति ने अगले वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य तीन प्रतिशत रखने की सिफारिश की है।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL) 7509975361, (PATNA) 7463950774, (DIBRUGARH) 7086708270, www.ksgindia.com

क्या है

1. सरकार ने एफआरबीएम कानून की समीक्षा के लिए एन के सिंह की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति का गठन किया था। सरकार ने इस समिति को इस बिन्दु पर भी विचार करने को कहा था कि क्या सरकार को राजकोषीय घाटे का लक्ष्य तय करना चाहिए या फिर एक रेंज निर्धारित करनी चाहिए।
2. सरकार एफआरबीएम कानून के संबंध में समिति की सिफारिशों पर विचार करेगी और उसके बाद उचित कदम उठाएगी। हालांकि सूत्रो का कहना है कि सरकार समिति की कुछ सिफारिशों को आम बजट में ही जगह दे सकती है। यह पूछे जाने पर कि रिपोर्ट कब सार्वजनिक की जाएगी तो सूत्रों ने कहा कि इस बात का फैसला सरकार को करना है।
3. वित्त मंत्री को रिपोर्ट सौंपते वक्त आरबीआइ गवर्नर उर्जित पटेल, पूर्व वित्त सचिव सुमित बोस, मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम और एनआइपीएफपी के निदेशक राथिन राय भी मौजूद थे।
4. एन के सिंह समिति की रिपोर्ट चार हिस्सों में है। पहले हिस्स में राजकोषीय नीति, राजकोषीय रोडमैप, अंतरराष्ट्रीय अनुभव और इससे जुड़ी सिफारिशें हैं।
5. दूसरे हिस्से में ओईसीडी, विश्व बैंक और आइएलओ सहित विभिन्न अंतरराष्ट्रीय अनुभवों को समाहित किया गया है।
6. तीसरे हिस्से में केंद्र और राज्यों से जुड़े मुद्दों को जगह दी गयी है। रिपोर्ट के चौथे हिस्से में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों की राय दी गयी है।
7. सरकार ने मई 2016 में इस समिति का गठन किया था। समिति को अपनी रिपोर्ट 31 अक्टूबर तक सौंपनी थी हालांकि बाद में सरकार ने समिति को चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों और व्यय प्रबंधन आयोग की सिफारिशों पर भी विचार करने का जिम्मा सौंपा जिसके बाद समिति ने अब रिपोर्ट दी है।

इस बार सीएसआर में ज्यादा खर्च हुए

कंपनियों ने बीते वित्त वर्ष में कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) से जुड़े कार्यो पर ज्यादा खर्च किया। इस तरह की गतिविधियों में उनका खर्च 22 फीसद बढ़ गया। यह व्यय 8,300 करोड़ रुपये रहा। क्रिसिल फाउंडेशन की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई।

रिपोर्ट के मुताबिक

1. कंपनियों की ओर से ज्यादा धन शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य देखभाल और साफ-सफाई जैसी पहलों पर खर्च किया गया। वित्त वर्ष 2015-16 में सीएसआर पर कुल व्यय 2,500 करोड़ रुपये से बढ़कर 8,300 करोड़ रुपये हो गया। हालांकि, आवश्यक दो फीसद व्यय के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अब भी 1,835 करोड़ रुपये की जरूरत है।
2. बीते वित्त वर्ष में बीएसई पर सूचीबद्ध 4,887 कंपनियों के 30 फीसद यानी 1,505 कंपनियों ने सीएसआर के लक्ष्य को पूरा किया है।
3. इस तरह की कंपनियों की संख्या 133 रही जिन्होंने सीएसआर पर एक पैसा खर्च नहीं किया या अपने सीएसआर एजेंडा को रोककर रखा हुआ है। वित्त वर्ष 2014-15 में ऐसा करने वाली 200 कंपनियां थीं।
4. कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कॉरपोरेटों को अपने पिछले तीन साल के शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत सीएसआर गतिविधियों पर खर्च करना आवश्यक है।

विज्ञानं आर तकनोकी

डिजिटल ट्रांजैक्शन पर राज्यों की रैंकिंग

डिजिटल ट्रांजैक्शन को लेकर केंद्र सरकार गंभीरता दिखाते हुए इस दिशा में बड़ी पहल करने जा रही है। अब नीति आयोग डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने वाले राज्यों को रैंकिंग देगा। इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए आयोग ने राज्यों से 10 दिन के भीतर डिजिटल ट्रांजेक्शन का ब्योरा मांगा है।

क्या है

1. नीति आयोग ने राज्यों से कहा है कि वे अगले 10 दिनों में डिजिटल ट्रांजैक्शन का डाटा जमा करें। इससे कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए उठाए गए कदमों के आधार पर रैंकिंग दी जा सकेगी। आठ नवंबर को लिए

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL) 7509975361, (PATNA) 7463950774, (DIBRUGARH) 7086708270, www.ksgindia.com

गए नोटबंदी के फैसले के बाद केंद्र सरकार डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए पहले भी कई पहल कर चुकी है।

2. नोटबंदी के बाद सरकार ने डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहन के लिए कई कदम उठाए हैं। केंद्र ने पिछले महीने कैशलेस ट्रांजैक्शन को प्रोत्साहन के लिए दैनिक, साप्ताहिक और मेगा पुरस्कारों की घोषणा की थी।

3. इसके तहत सरकार 25 दिसंबर से उपभोक्ताओं और दुकानदारों वगैरह को डिजिटल भुगतान पर 340 करोड़ रुपये के पुरस्कार देगी। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 दिसंबर को एक देशी पेमेंट ऐप भीम को भी लांच किया था। इसके जरिये मोबाइल पर तेजी से और सुरक्षित ढंग से कैशलेस ट्रांजैक्शन किए जा सकते हैं।

4. अक्टूबर, 2015 तक देश में 61.5 करोड़ डेबिट और 2.3 करोड़ क्रेडिट कार्ड धारक थे। नोटबंदी के बाद मोबाइल वॉलेट, यूएसएसडी और रुपे जैसे डिजिटल भुगतान चौनलों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। यूएसएसडी के तहत मुख्य रूप से मोबाइल शॉर्ट कोड मैसेज का इस्तेमाल फीचर फोन के जरिये बैंकिंग सेवाओं के लिए किया जाता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 25 दिसंबर को यूएसएसडी ट्रांजेक्शन 5,135 प्रतिशत बढ़कर 5,078 लेनदेन प्रतिदिन पर पहुंच गए।

BHIM App से जुड़ा 'आधार पे'

सरकार ने भीम एप के साथ आधार को जोड़ दिया है। इसके साथ ही इसी महीने बायोमेट्रिक आधारित आधार पे भुगतान मॉड्यूल को लॉन्च करने जा रही है। सरकार देश में डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए इसे जल्द से जल्द लागू करने की रणनीति बना रही है।

क्या है

1. इस बायोमेट्रिक आधारित भुगतान प्रणाली के जरिए पेमेंट करने के साथ पेमेंट रिसीव भी कर सकेंगे। श्आधार पेश के जरिये लोग अपने स्मार्टफोन से सिर्फ फिंगरप्रिंट्स का इस्तेमाल कर ट्रांजैक्शन्स कर सकते हैं। बता दें कि आधार पे पहले से चल रहे पेमेंट सिस्टम। EPS का मर्चेंट वर्जन है।

2. इस सेवा को नए वित्त वर्ष यानी अप्रैल से चालू किया जा सकता है। करीब 14 बैंकों ने इस सेवा को चालू करने पर सहमति जता दी है। सरकार का मानना है कि इससे देश में कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा मिलेगा।

3. आधार के जरिए देश के 1.11 बिलियन लोगों के पास यूनिक नंबर मौजूद हैं। वहीं देश के 390 मिलियन बैंक अकाउंट आधार कार्ड से जुड़े हुए हैं। सेवा का लाभ पाने के लिए आपके बैंक अकाउंट नंबर का आधार से लिंक होना जरूरी है। अगर आपका अकाउंट नंबर आधार नंबर से लिंक नहीं है तो आप आधार पे के जरिए पेमेंट नहीं कर पाएंगे।

4. गौरतलब है कि फिलहाल बैंक डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए टू स्टेप वेरिफिकेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। जल्द ही आधार पे पासवर्ड और पिन के जरिए होने वाले ऑनलाइन और कार्ड ट्रांजैक्शन्स की जगह ले लेगा। इस एप को ऐसे डिजाइन किया गया है जिससे कोई अशिक्षित व्यक्ति भी सिर्फ फिंगरप्रिंट्स के जरिए डिजिटल ट्रांजेक्शन कर पाएगा। इससे ट्रांजेक्शन के लिए कस्टमर को अपना आधार नंबर, बैंक का नाम (जिससे पैसा कटवाना है) और फिंगरप्रिंट देना होगा।

5. फिलहाल आधार पे पर मर्चेंट्स का विश्वास जगाने की कोशिश की जा रही है। आधार पे के जरिए पेमेंट्स लेने के लिए दुकानदारों को 2000 रुपए की बायोमेट्रिक डिवाइस भी लेनी पड़ेगी। सरकार ऐसे मॉडल पर काम कर रही है जिससे डिवाइस की कीमत को मर्चेंट्स से धीरे-धीरे वसूला जाए। सरकार का मानना है कि मर्चेंट्स तभी इसके इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित होंगे।

6. आधार पे को लेकर उठ रहे सुरक्षा के सवालों के जवाब में पांडे ने कहा कि यह किसी और डिजिटल पेमेंट के तरीके से कई ज्यादा सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि कस्टमर का बैंक अकाउंट और मर्चेंट का बैंक अकाउंट आधार से लिंक होने के कारण इसके गलत प्रयोग की गुंजाइश कम होगी। उन्होंने कहा, 'फिंगरप्रिंट को कॉपी नहीं किया जा सकता। अगर कोई मर्चेंट या कस्टमर फिंगरप्रिंट्स का मिस्यूज करने की कोशिश करता है तो वह तुरंत पकड़ा जा सकेगा क्योंकि ऐप के जरिए ट्रांजैक्शन्स की लोकेशन के बारे में बैंक को जानकारी होगी।'

ब्रह्मांड में हैं दो हजार करोड़ आकाश गंगाएं

ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं पर किए गए शोध में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में दो हजार आकाशगंगा होने की बात कही है। हब्बल समेत दुनिया भर के अन्य टेलीस्कोप की मदद से इसका पता लगाया गया है। पूर्व के आकलन में सौ से दौ सौ अरब आकाशगंगाएं होने की बात सामने आई थी।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL) 7509975361, (PATNA) 7463950774, (DIBRUGARH) 7086708270, www.ksgindia.com

क्या है

1. नॉटिंघम विश्वविद्यालय के शोधकर्ता क्रिस्टोफर कांसलाइस के मुताबिक, मौजूदा तकनीक की मदद से इनमें से महज दस फीसद आकाशगंगाओं का अध्ययन ही संभव है।
2. बेहतर और शक्तिशाली टेलीस्कोप विकसित होने पर ही बाकी के बारे में विस्तृत जानकारी मिल सकेगी। टेलीस्कोप की मदद से प्राप्त पेंसिल बीम इमेज को 3डी में परिवर्तित किया गया। इससे आकाशगंगा के घनत्व और अंतरिक्ष के एक छोटे से क्षेत्र में इसकी संख्या के बारे में पता लगाना संभव हो सका।
3. नई आकाशगंगाओं में अधिकांश कम द्रव्यमान के हैं। इस अभियान में लीडन यूनिवर्सिटो (नीदरलैंड्स) और एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के शोधकर्ता भी शामिल थे।
4. आकाशगंगा का पता वहां से आने वाली प्रकाश की किरणों के जरिये लगाया जाता है।

विविध

ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2017

ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स ने साल 2017 की सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में जर्मनी को पहला स्थान दिया गया है और अफगानिस्तान को सबसे अंतिम स्थान दिया गया है। ऑर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्सो ने दुनिया के 199 देशों के पासपोर्ट की पावर के बारे में बताया है। इस इंडेक्स में संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 193 सदस्य देशों और 6 क्षेत्रों (ताइवान, मकाओ, हॉन्ग-कॉन्ग, कोसोवो, फिलिस्तीनी क्षेत्र और वैटिकन) के पासपोर्ट्स को शामिल किया गया है। 157 वीजा फ्री स्कोर के साथ जर्मनी का पासपोर्ट सूची में शीर्ष पर और सिंगापुर और स्वीडन को दूसरा स्थान मिला है। सिंगापुर ने दक्षिण कोरिया को पछाड़कर एशियाई देशों में सबसे ताकतवर पासपोर्ट होने का तमगा हासिल किया है। सिंगापुर के पासपोर्ट का वीजा फ्री स्कोर 156 है। वहीं ताकतवर पासपोर्ट्स की लिस्ट में अफगानिस्तान सबसे नीचे है। उसे पासपोर्ट का वीजा फ्री स्कोर मात्र 23 है। सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की ग्लोबल रैंकिंग में भारत का वीजा फ्री स्कोर 46 है जिस पर इसे दुनिया का 78वां शक्तिशाली पासपोर्ट माना गया है। इस लिस्ट में चीन की रैंक 58वीं और पाकिस्तान की 94वीं है।

इस आधार पर तय होती है रैंकिंग

1. किसी राष्ट्र के पासपोर्ट का किसी दूसरे देश में कितनी आसानी से आना-जाना
2. कितने देशों में ये पासपोर्ट वीजा फ्री एंट्री पा सकते हैं या वीजा ऑन अराइवल पा सकते हैं। इसके आधार पर इन्हें वीजा फ्री स्कोर दिया जाता है।

टॉप 10 ताकतवर पासपोर्ट्स

1. जर्मनी- 157
2. सिंगापुर, स्वीडन- 156
3. फ्रांस, स्पेन, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए- 155
4. जापान, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, इटली, ऑस्ट्रिया, लग्जमबर्ग, पुर्तगाल, - 154
5. मलयेशिया, आयरलैंड, कनाडा, न्यू जीलैंड-153
6. ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, दक्षिण कोरिया - 152
7. चेक गणराज्य, आइसलैंड- 151
8. हंगरी- 150
9. माल्टा, पोलैंड- 150
10. स्लोवानिया, स्लोवाकिया, लिथुआनिया, लाटविया- 148

सबसे कमजोर पासपोर्ट्स वाले देश

1. अफगानिस्तान- 23
2. पाकिस्तान- 26

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL) 7509975361, (PATNA) 7463950774, (DIBRUGARH) 7086708270, www.ksgindia.com

3. इराक- 28
4. सीरिया- 29
5. सोमालिया- 30
6. दक्षिणी सूडान, इथियोपिया- 34
7. श्री लंका, बांग्लादेश- 35
8. ईरान, सूडान- 36
9. फिलिस्तीन, नेपाल, लीबिया- 37
10. लेबनान- 38

सम्पति पर ऑक्सफैम की रिपोर्ट

देश की 58% संपत्ति पर यहां की महज 1% आबादी का कब्जा है। यह आंकड़ा 50 प्रतिशत के वैश्विक आंकड़े से ज्यादा है। ऑक्सफैम ने अपनी स्टडी का यह नतीजा तब पेश किया है जब वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की सालाना बैठक में शामिल होने दुनियाभर के दौलतमंद दावोस पहुंचनेवाले हैं। स्टडी में सामने आया है कि भारत के सिर्फ 57 महाधनवान लोगों के पास करीब 15 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति है। इतनी ही राशि देश के उन 70 प्रतिशत लोगों के पास है जो आर्थिक हैसियत के हिसाब से निचले पायदान पर खड़े हैं।

स्टडी के मुताबिक

1. वैश्विक स्तर पर तो स्थिति और भी खराब है। स्टडी कहती है कि दुनिया के सिर्फ और सिर्फ 8 महाधनवानों के पास इतनी दौलत है जितनी आधी गरीब आबादी के पास है। मतलब, इन 8 महाधनवानों के पास दुनिया की 50 प्रतिशत आबादी के बराबर की संपत्ति है।
2. भारत में कुल 84 अरबपति हैं जिनके पास करीब 16 लाख करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति है। अरबपतियों को इस सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) के मालिक मुकेश अंबानी कुल 1.31 लाख करोड़ रुपये की कुल संपत्ति के साथ शीर्ष पर हैं। उनके बाद दिलीप सांघवी (करीब 1.13 लाख करोड़) और अजीम प्रेमजी (1.02 लाख करोड़) का नंबर है।
3. देश की कुल संपत्ति करीब 211 लाख करोड़ रुपये आंकी गई है जबकि दुनिया की कुल संपत्ति करीब 17427 लाख करोड़ रुपये बताई गई है। दुनिया की इस संपत्ति में करीब 4500 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति महज 8 महाधनवानों के पास है।
4. इस सूची में बिल गेट्स करीब 5 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ शीर्ष पर हैं। इस सूची मेंअमांसियो ऑर्तेगा (करीब 4.5 लाख करोड़ रुपये) दूसरे जबकि वॉरेन बफेट (करीब 4.14 लाख करोड़ रुपये) तीसरे नंबर पर हैं।
5. 'एन इकॉनमी फॉर 99 पर्सेंट' के नाम से जारी इस स्टडी रिपोर्ट में ऑक्सफेम ने ह्यूमन इकॉनमी के निर्माण की वकालत की है जिससे हरेक व्यक्ति को फायदा होगा, ना कि मुट्ठीभर सुविधासंपन्न लोगों को।
6. साल 2015 से महाधनवान 1 प्रतिशत लोगों ने दुनिया के बाकी 99 प्रतिशत लोगों के बराबर की संपत्ति पर कब्जा कर रखा है।

दुनिया की सबसे हल्की घड़ी

ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने वंडर मैटीरियल के नाम से मशहूर ग्रेफीन की मदद से अब तक की सबसे हल्की कलाई घड़ी बनाने में सफलता हासिल की है। इसका वजन महज 40 ग्राम है। इसकी गुणवत्ता आम घड़ी की तुलना में बेहतर है। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने घड़ी निर्माता कंपनी रिचर्ड मिल और मैक्लरीन एफ-1 के साथ मिलकर इसे बनाया है। इसे आरएम 50-03 का नाम दिया गया है। घड़ी में इस्तेमाल ग्रेफीन मिश्रण को ग्राफ टीपीटी कहा जाता है। यह सामान्य तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थों से बहुत हल्का है।

क्या है

1. ग्रेफीन महज एक अणु तक ही मोटा होता है। पहली बार 2004 में इसका पता लगाया गया था।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL) 7509975361, (PATNA) 7463950774, (DIBRUGARH) 7086708270, www.ksgindia.com

2. इसकी मदद से उच्च गुणवत्ता वाले वाहन और विमान के उपकरण के अलावा मुड़ने वाले मोबाइल फोन, टैबलेट और बिजली स्टोर करने वाले उपकरण भी बनाए जा सकते हैं।
3. वैज्ञानिकों ने घड़ी की पट्टी में ग्रेफीन की अतिरिक्त मात्रा मिलाकर वजन को कम करने में सफलता पाई है। एक्स-रे टोमोग्राफी (आंतरिक उपकरणों का चित्र) और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से इसके गुणवत्ता की जांच की गई। वजन कम होने के अलावा यह सामान्य घड़ियों की तुलना में ज्यादा समय तक चलने में भी सक्षम है।
4. प्रोफेसर रॉबर्ट यंग ने बताया कि भविष्य में 40 ग्राम से भी कम वजन वाली घड़ी का निर्माण संभव हो सकेगा। ऐसी घड़ी के अन्य उपकरणों में ग्रेफीन को मिलाने से संभव होगा।

चंद्रमा की सतह पर वॉक करने वाले यूगीन नहीं रहे

चांद पर आखिरी बार कदम रखने वाले अंतरिक्ष यात्री यूगीन सरनन का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वह अपोलो 17 के सदस्य होने के साथ-साथ इस मिशन कमांडर भी थे। चंद्रमा पर अमेरिका द्वारा भेजे गए तीसरे और आखिरी मिशन के इस सदस्य के निधन पर नासा ने शोक व्यक्त किया है। सरनन एक रिटायर्ड नौसेना अधिकारी थे। परिजनों के मुताबिक वह कुछ समय से बीमार चल रहे थे।

क्या है

1. सरनन के मिशन के दौरान चांद से पृथ्वी की बेहतरीन तस्वीरें खींची गई थीं। जिसे ब्लू मार्बल भी कहा गया। मल्टी कलर वाली इन इमेजेस में धरती के रंग बिरंगे रूप का अदभुत नजारा कैमरे की आंखों से देखा गया था।
2. सरनन का जन्म 1934 में शिकागो में हुआ था। उन्होंन 1956 में इंडियाना परड्यू यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। केलीफोर्निया यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री करने के बाद वह वर्ष 1963 में नासा से जुड़ गए। उन्होंने जेमिनी और अपोलो मिशन में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई थी।
3. वह 7 दिसंबर 1972 को अपन मिशन के तहत रवाना हुए थे। इस दौरान उन्होंने स्पेस में करीब 566 घंटे और 15 मिनट (12 दिन, 13 घंटे, 51 मिनट, 59 सेकंड) बिताए। इसमें से करीब 73 घंटे उन्होंने चांद पर बिताए थे।
4. वर्ष 1976 में नासा से रिटायर होने के बाद वह स्पेस शटल फ्लाइट्स के दारान की जाने वाली कॉमेंट्री करने लगे थे।
5. वर्ष 2013 में उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री को भी प्रदर्शित किया गया था। गौरतलब है कि पिछले वर्ष ही धरती की कक्षा का पहली बार चक्कर लगाने वाले अंतरिक्ष यात्री जॉन ग्लेन का भी निधन हो गया था।
6. वह 1959 में भेजे गए स्पेस मिशन के आखिरी सदस्य थे।

राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2016

वर्ष 2016 के राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए 25 बच्चों का चयन हुआ है। इनमें 12 लड़कियां और 13 लड़के हैं। चार बच्चों को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 जनवरी को पुरस्कार देंगे। बच्चों को गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने और जीप की सवारी करने का भी मौका मिलेगा।

क्या है

1. प्रतिष्ठित भरत अवॉर्ड अरुणाचल प्रदेश की तार पीजू (8) को मरणोपरांत दिया जाएगा।
2. गीता चोपड़ा अवॉर्ड पश्चिम बंगाल की तेजस्विता प्रधान (18)और शिवानी गोंड (17) को संयुक्त रूप से दिया जाएगा। दोनों ने बिना डरे पुलिस और एनजीओ की मदद कर अंतरराष्ट्रीय सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया था।
3. प्रतिष्ठित संजय चोपड़ा अवॉर्ड देहरादून (उत्तराखंड) के 15 वर्षीय मास्टर सुमित ममगाई को दिया जाएगा। सुमित ने चचेर भाई को तेंदुए से बचाया था। अपनी जान देकर दो बच्चियों को डूबने से बचाने वाली मिजोरम की कुमारी रोलुआपुई (13), कार दुर्घटना में खुद की जान देकर चचेरे भाई की जान बचाने वाली मिजोरम की एच लालरियातपुई (13) और घर के पास लगी आग में से कई पशुआं की जान बचाने वाले छत्तीसगढ़ के मास्टर तुषार वर्मा (15) को बापू गयाधनी अवॉर्ड दिया जाएगा।
4. राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार पाने वालों में तीन बहादुर बच्चे दिल्ली के भी हैं। इनमें मालवीय नगर निवासी भाई-बहन अक्षिता शर्मा (16) और अक्षित शर्मा (13) ने चोरी करने के लिए घर में घुसे दो बदमाशों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए एक को धर दबोचा था। पीतमपुरा गांव निवासी नमन (16) ने सोनीपत में यमुना में डूबते एक बच्चे की जान बचाई थी।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL) 7509975361, (PATNA) 7463950774, (DIBRUGARH) 7086708270, www.ksgindia.com

5. राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार पाने वाले अन्य बहादुर बच्चों में हिमाचल प्रदेश के मंडी निवासो मास्टर प्रफुल्ल शर्मा, राजस्थान के मास्टर सोनू माली, लखनऊ की कुमारी अंशिका पांडेय, महाराष्ट्र की कुमारी निशा दिलीप पाटिल, कर्नाटक की कुमारी सिया वामनसा, मणिपुर के मास्टर सदानंद सिंह, केरल निवासी मास्टर आदित्यन पिल्लई, अखिल के शिबू और कुमारी बदरुनिशा, असम क मास्टर टंकेश्वर पेगू, छत्तीसगढ़ की कुमारी नीलम ध्रुव, नगालैंड निवासी थंगिलमंग लंकिम, ओडिशा निवासी मास्टर मोहन शेट्टी और जम्मू-कश्मीर की कुमारी पायल देवी (मरणोपरांत) शामिल हैं।
6. इन सभी बहादुर बच्चों को 50 हजार रुपये, प्रशस्ति पत्र और मेडल प्रदान किया जाएगा। सभी की शिक्षा-दीक्षा का खर्च परिषद द्वारा वहन किया जाएगा।

क्रिस्चन पर्सनल लॉ के तहत तलाक को कानूनी मान्यता नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि चर्च संबंधी ट्राइब्यूनल द्वारा कैनन लॉ (क्रिस्चन पर्सनल लॉ) के तहत तलाक देना कानूनी तौर पर मान्य नहीं है। कार्ट ने कहा कि डिवॉर्स एक्ट के बाद क्रिस्चन पर्सनल लॉ के तहत तलाक नहीं हो सकता बल्कि डिवॉर्स ऐक्ट प्रभावी होगा। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि क्रिस्चन कपल का कानूनी रूप से तलाक तभी मान्य होगा जब वह भारतीय कानून के तहत लिया गया हो। पर्सनल लॉ संसद द्वारा बनाए गए कानून को ओवरराइड नहीं कर सकता। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उस पीआईएल को भी खारिज कर दिया जिसमें चर्च कोर्ट द्वारा दिए गए तलाक के मामले को कानूनी मान्यता दिए जाने की मांग की गई थी।

क्या है

1. चीफ जस्टिस जेएस खेहर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने इस मामले मं कर्नाटक कैथलिक असोसिएशन के पूर्व प्रेजिडेंट सी पाइस की ओर से दाखिल याचिका को खारिज कर दिया।
2. कोर्ट ने कहा कि 1996 में सुप्रीम कोर्ट से मॉली जोसेफ बनाम जॉर्ज सेबेस्टियन के मामले में पहले ही फैसला दिया जा चुका है और इससे संबंधित व्यवस्था दी जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डिवॉर्स ऐक्ट आने के बाद से पर्सनल लॉ के तहत शादी खत्म करने के प्रावधान का कोई कानूनी प्रभाव नहीं है।
3. याचिकाकर्ता ने अपनी अर्जी में कहा था कि चर्च द्वारा तलाक को मान्यता दी जानी चाहिए क्योंकि ये पर्सनल लॉ के तहत होता है और इस भारतीय कानून के तहत स्वीकार किया जाना चाहिए। उनकी दलील दी थी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत जिस तरह से तीन तलाक को मंजूरी दी जाती है उसी तरह से उन्हें भी मान्यता मिलनी चाहिए।
4. सी पाइस की ओर से पेश सीनियर ऐडवोकेट सॉली सोराबजी ने कहा कि जब मौखिक ट्रिपल तलाक के मामले को कानूनी मान्यता मिली हुई है तो फिर कैनन लॉ (क्रिस्चन पर्सनल लॉ) के तहत दिए गए तलाक को क्यों वैधता नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कई कैथलिक क्रिस्चन जिन्होंने क्रिस्चन कोर्ट द्वारा तलाक लिए जाने के बाद दोबारा शादी की है उन्हें बाइगेमी मामले (पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी करना) में क्रिमिनल केस का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि क्रिमिनल और सिविल कोर्ट उसे मान्यता नहीं देते।
5. वहीं केंद्र सरकार ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि कैनन लॉ, इंडियन क्रिस्चन मैरिज एक्ट 1872 और डिवॉर्स एक्ट 1869 पर प्रभावी नहीं हो सकता। चूंकि शादी खत्म करने संबंधी आदेश पारित करने का अधिकार सिर्फ कोर्ट को है ऐसे में चर्च ट्राइब्यूनल सहित अन्य अथॉरिटी को ऐसा अधिकार नहीं है कि वह शादी को खत्म करने का आदेश पारित करें।
6. केंद्र ने कहा कि इंडियन डिवॉर्स एक्ट शादी को खत्म करने के प्रावधान की व्याख्या करता है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही व्यवस्था दी हुई है कि चर्च संबंधी ट्राइब्यूनल द्वारा शादी खत्म करने संबंधी आदेश कोर्ट के लिए बाध्यकारी नहीं है।
7. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1996 के फैसले के मद्देनजर याचिका खारिज की जाती है। कोर्ट ने कहा कि उस फैसले में क्रिस्चन में शादी और तलाक के प्रावधान को साफ किया गया था। कोर्ट ने कहा कि अगर संसद कोई कानून बनाती है, फिर वह कानून किसी समुदाय के पर्सनल लॉ से संबंधित ही क्यों न हो, तो पार्लियामेंट का कानून ही प्रभावी होगा न कि कोई पर्सनल लॉ या परंपरा। अदालत ने कहा कि चर्च कोर्ट को इस तरह का आदेश पारित करने का अधिकार नहीं है। तलाक देने का अधिकार सिर्फ कोर्ट को है।

हिमाचल की दूसरी राजधानी

हिमाचल प्रदेश के सीएम वीरभद्र सिंह ने धर्मशाला को राज्य की दूसरी राजधानी घोषित किया। धर्मशाला धौलाधार पर्वत श्रंखला पर स्थित है। 1960 में दलाई लामा ने इस शहर को अपना मुख्यालय बनाया था, तभी से वह यहां से तिब्बत की निर्वासित सरकार चला रहे हैं।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL) 7509975361, (PATNA) 7463950774, (DIBRUGARH) 7086708270, www.ksgindia.com

क्या है

1. सर्दियों में अपने प्रवास पर धर्मशाला आए मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा का अपना इतिहास और महत्व है। साथ ही यह राज्य की दूसरी राजधानी बनने का हकदार है। उन्होंने कहा कि राज्य के निचले इलाकों जैसे कांगड़ा, चंबा, हमीरपुर और ऊना जिले में इस शहर का अपना महत्व है।
2. इस क्षेत्र के लोगों को अब इस विशेष दर्जे का फायदा होगा और उन्हें अपने काम के लिए शिमला नहीं जाना होगा। सीएम वीरभद्र सिंह ने कहा कि धार्मिक और अडवेंचर टूरिज्म के महत्व के चलते धर्मशाला का केवल भारत के नक्शे पर ही नहीं बल्कि दुनिया के नक्शे पर भी अहम स्थान है।
3. धर्मशाला को दलाई लामा का घर बताते हुए राज्य के सीएम ने कहा कि दुनिया के प्रतिष्ठित लोगों का यहां आना-जाना लगा रहता है। उन्होंने कहा कि दलाई लामा के चलते पूरी दुनिया से कई लोग इस क्षेत्र के दौरे पर आते हैं।
4. सीएम ने कहा कि पहली बार 2005 में विधानसभा के शीतकालीन सत्र का शिमला से बाहर आयोजन किया गया था।
5. धर्मशाला के तपोवन में पहले से ही एक विधानसभा भवन है। इसकी नींव भी 2006 में वीरभद्र सिंह के समय में ही रखी गई है। यहा पर विधानसभा के 12 शीतकालीन सत्र का आयोजन हो चुका है।

साइना नेहवाल ने जीता मलयेशिया मास्टर्स ग्रां प्री गोल्ड

शीर्ष भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने 120,000 डॉलर ईनामी राशि के मलयेशिया मास्टर्स ग्रां प्री गोल्ड का खिताब अपने नाम कर लिया है। फाइनल में साइना ने थाइलैंड की पॉर्नपावी चोचुवोंग को सीधे गेम में मात दी। साइना ने 22-20, 22-20 से जीत दर्ज कर खिताब अपने नाम किया। साइना पिछले साल लगातार चोट से जूझ रही थीं। रियो ओलिंपिक 2016 के बाद उनकी सर्जरी भी हुई थी।

क्या है

1. इससे पहले, साइना ने टूर्नमेंट के दूसरे सेमीफाइनल में हॉन्ग कॉन्ग की यिप पुई यिन को 21-13, 21-10 से मात देकर फाइनल में प्रवेश किया, वहीं पोर्नपावी ने पहले सेमीफाइनल मैच में चेयुंग गान यी को 21-19, 20-22, 21-18 से मात देकर फाइनल में जगह बनाई थी।
2. पहली गेम साइना ने 22-20 से जीता हासिल की थी। दूसरे गेम में साइना 20-16 से आगे चल रही थीं लेकिन इसके बाद चोचुवोंग ने वापसी करते हुए स्कोर को 20-20 से बराबर कर लिया। इसके बाद साइना ने संयम बनाए रखा और गेम अपने नाम किया।
3. विश्व की 10वीं वरीयता प्राप्त साइना और 67वीं वरीयता प्राप्त पोर्नपावी का पहली बार आमना-सामना हुआ था, जिसमें भारतीय खिलाड़ी ने जीत हासिल की। करियर के लिए खतरनाक घुटने की चोट से उबरने के बाद साइना नेहवाल ने मलयेशिया मास्टर्स का खिताब जीता और इस दिग्गज भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने इसे काफी कड़ा और भावनात्मक सफर करार दिया। साइना ने इस खिताबी मुकाबले में थाईलैंड की पोर्नपावी चोचुवोंग को 46 मिनट में 22-20, 22-20 से हराने के बाद कहा, 'घुटने के ऑपरेशन क 4 महीने के भीतर खिताब जीतना मेरे लिए काफो कड़ा और भावनात्मक सफर था।'
4. साइना के करियर का यह कुल 23वां और पिछले साल ऑस्ट्रेलिया ओपन के बाद पहला खिताब है। लंदन ओलिंपिक 2012 की कांस्य पदक विजेता साइना ने इस मुश्किल चरण में समर्थन के लिए अपने कोचों और सहयोगी स्टाफ को धन्यवाद दिया।

'ला ला लैंड' को ऑस्कर की 14 श्रेणियों में नामांकन

फिल्मी दुनिया का नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले ऑस्कर के लिए नामांकनों की घोषणा की गई। हॉलीवुड की रोमांटिक फिल्म श्ला ला लैंडश को 89वें ऑस्कर पुरस्कारों के लिए रिकॉर्ड 14 श्रेणियों में नामांकन मिला है। इससे पहले 'टाइटेनिक' और 'ऑल अबाउट ईव' को 14 श्रेणियों में नामांकन मिल चुका है। अभिनेत्री मेरिल स्ट्रीप ने 20वीं बार नामांकन हासिल कर अपने ही रिकार्ड में सुधार किया।

क्या है

1. 'ला ला लैंड' के निर्देशक डेमियन चौजेल को सर्वश्रेष्ठ निर्माता के तौर पर नामांकन मिला। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता व अभिनेत्री का नामांकन भी दिया गया। विज्ञान आधारित फिल्म 'अराइवल' व 'मूनलाइट' को आठ-आठ श्रेणियों में नामांकन मिला है।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL) 7509975361, (PATNA) 7463950774, (DIBRUGARH) 7086708270, www.ksgindia.com

2. आलोचनाओं का सामना कर रही ऑस्कर एकेडमी ने इस साल नामांकन में अधिकतम विविधता रखने का प्रयास किया है।
3. एकेडमी ने डेंजेल वाशिंगटन, ओक्टाविया स्पेंसर, वियोला डेविस, रुथ नेगा, महेरशाला अली, भारतीय मूल के ब्रिटिश अभिनेता देव पटेल सरीखे अभिनेताओं को नामांकन दिया है।
4. भारत के ऑस्कर विजेता संगीतकार एआर रहमान ऑस्कर की दौड़ से बाहर हो गए हैं। ऑस्कर नामांकन की सूची में उनका नाम नहीं है। रहमान को इस साल श्पेले : बर्थ ऑफ ए लीजेंडश के लिए नामांकन मिलने की उम्मीद थी।

पद्म सम्मान का एलान

कुछ न कुछ कारणों से अक्सर विवादों या चर्चा में रहने वाला पद्म पुरस्कार पर इस बार राजनीतिक मंशा, पैरवी या जनसंपर्क के दाग से दूर है। दिल्ली जैसे बड़े शहरों के प्रभाव को भी झुठलाता है। अठारह सौ नामांकनों में से 89 को चुनने में केवल उनकी विलक्षणता, जनसेवा भाव और समाज के लिए योगदान को ही आधार बनाया गया है। ऐसी विभूतियों को चुना गया है जो श्रेय पाने की होड़ से दूर थे लेकिन लगातार अनूठी पहल कर समाज को समृद्ध करते रहे।

क्या है

1. पहली बार पद्म पुरस्कारों के लिए आनलाइन नामांकन प्रक्रिया में कुल 4000 लोगों के लिए 18000 से अधिक नामांकन किये गए।
2. इनमं से केवल 89 लोगों का पद्म पुरस्कार के लिए चयन किया गया। पुरस्कारों को राजनीतिक भेदभाव से परे रखे जाने का सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी और सुंदरलाल पटवा के साथ-साथ राकांपा के वरिष्ठ नेता शरद पवार और पीए संगमा को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है।
3. इनमें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा और पूर्व लोकसभाध्यक्ष पीए संगमा को मरणोपरांत यह सम्मान दिया गया है। इसके साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल के भाई और पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल को पद्म श्री से सम्मानित किया गया है।
4. पद्म पुरस्कारों के चयन में कहीं भी पांच राज्यों में चुनावी छाया नजर नहीं आती है। इसके बजाय पूरे देश से अपने-अपने क्षेत्र में विशिष्ट योगदान करने वालों को इसमें स्थान मिला है।
5. संप्रग सरकार के दौरान 2005 से 2014 तक पद्म पुरस्कार पाने वालों में औसतन 24 दिल्ली के होते थे। जो इन पुरस्कारों के लिए होने वाले लॉबिंग का साफ संकेत है। लेकिन इस बार दिल्ली के केवल पांच लोगों को इसके लिए चुना गया है। उनमें भी ऐसे लोग दूर रहे जिनकी दुकानें बड़ी थीं।
6. जनता के बीच असली काम करने वाले को ही जगह मिली है। यही वजह है कि सूची में दिल्ली के बड़े-बड़े अस्पतालों के डाक्टरों के नाम गायब हैं। इसके बजाय इंदौर में पिछले सात दशकों से रोगियों का मुफ्त इलाज करने वाली 91 साल की डाक्टर भक्ति यादव, हाईवे दुर्घटनाओं में घायल लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने वाले वड़ोदरा के डाक्टर सुब्रतो दास, ओडिशा के दूरदराज गांव में जनजातीय परिवार में पैदा होने वाले चंडीगढ़ के किडनी रोग विशेषज्ञ डाक्टर मुकुट मिंज को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है।
7. पिछले तीन दशकों में डाक्टर मुकुट मिंज 3400 से अधिक किडनी प्रत्यारोपित कर चुके हैं।
8. पहली बार पद्म पुरस्कारों में मशहूर फिल्मी हीरो-हीरोइनों के नाम गायब है। तीन पार्श्व गायकों को स्थान दिया गया है, जिनमें यशुदास, अनुराधा पौडवाल और कैलाश खेर शामिल हैं।
9. प्रसिद्धि के बजाय सरकार ने अनूठी पहल करने और राष्ट्रनिर्माण में अहम भूमिका निभाने वालों को जगह मिली है। उनमें सिल्क साड़ी बुनने वाली मशीन बनाने वाले, सूखाग्रस्त इलाके में अनार की लहलहाती फसल उगाने वाले और एक करोड़ से अधिक पेड़ लगाने वाले, कोलकाता में चार दशकों से मुफ्त में अग्निशमन विभाग में अपनी सेवा देने वाले लोग शामिल हैं। वहीं मधुबनी पेंटिंग को क्षेत्रीय सीमाओं से बाहर निकालकर अंतरराष्ट्रीय आर्ट तक पहुंचाने वाली बौआ देवी को भी सम्मानित किया गया है।

सूर्य नमस्कार को अमेरिकी कांग्रेस में मान्यता मिली

सूर्य नमस्कार यज्ञ या हेल्थ फॉर हयूमेनिटी योगाशन को इसके 10वें सालगिरह के मौके पर अमेरिकी कांग्रेस में मान्यता मिल गई है। इलिनॉयस के सांसद बिल फोस्टर ने सदन में कहा कि माननीय अध्यक्ष, मैं यहां हिंदू स्वयंसेवक संघ के 10वें हेल्थ फॉर हयूमेनिटी योगाशन या सूर्य नमस्कार यज्ञ को मान्यता देने के लिए खड़ा हूं।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL) 7509975361, (PATNA) 7463950774, (DIBRUGARH) 7086708270, www.ksgindia.com

क्या है

1. सूर्य नमस्कार सामान्य रूप से 10 चरणों वाली योग मुद्रा है जिसमें आसानी से सांस लेने की तकनीक सिखाई जाती है जो कि शरीर और मानसिक स्वास्थ्य को काफी लाभ पहुंचाता है।
2. हर साल दुनिया भर में हिंदू 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाते हैं, इस दिन को मौसम के बदलाव के रूप में देखा जाता है क्योंकि सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है।
3. इस अवसर पर 14 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक हिंदू स्वयंसेवक संघ योग फॉर हेल्थ, हेल्थ फॉर हयूमेनिटी योगाशन का आयोजन करते हैं।
4. फोस्टर ने कहा कि इस 16 दिवसीय कार्यक्रम में योग के बारे में जागरूकता फैलाई जाएगी और स्वस्थ तन और मन को पाने में इसके लाभों के बारे में बताया जाएगा।

दुनिया की छठी महाशक्ति भारत

वर्ष 2017 में भारत दुनिया के शीर्ष आठ महा शक्तिशाली देशों की सूची में छठे नंबर पर रहेगा। अमेरिका की एक शीर्ष फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने यह भविष्यवाणी की है। उसके अनुसार, इस सूची में चीन और जापान भारत से आगे, जबकि अमेरिका शीर्ष पर रहेगा। सूची में चीन और जापान संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर रखे गए हैं।

क्या है

1. रैंकिंग में भारत से आगे जो अन्य देश हैं, उनमें रूस चौथे और जर्मनी पांचवें स्थान पर है। महा शक्तिशाली देशों की सूची में ईरान की सातवीं और इजरायल की आठवीं रैंकिंग है।
2. आठ महाशक्तियों के बारे में जारी ताजा सालाना रिपोर्ट में मैगजीन 'द अमेरिकन इंटरेस्ट' ने कहा है, 'जापान की तरह, दुनिया की महाशक्तियों की सूची में अक्सर भारत को नजरअंदाज किया जाता रहा है। हालांकि वास्तविकता यह है कि उसका विश्व स्तर पर असाधारण दखल है।' इसमें कहा गया है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है।
3. विश्व में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोलने वाली आबादी भारत में है। वह एक विविध और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है।
4. इसमें कहा गया है, 'भू-राजनीतिक मोर्चे पर, बहुत से देश भारत को अपने पाले में करना चाहते हैं। चीन, जापान और अमेरिका अपनी पसंदीदा एशियाई सुरक्षा संरचना में भारत को सम्मिलित करना चाहते हैं।
5. वहीं, यूरोपीय संघ (ईयू) और रूस लाभकारी व्यापार और रक्षा करारों के लिए भारत को आमंत्रित करते हैं। मैगजीन के अनुसार, नोटबंदी के बाद पैदा आंतरिक समस्याओं और पाकिस्तान की हरकतों के बावजूद भारत 2016 में खुद को ऊंच स्तर पर रखने में सफल रहा।

भारतीय मूल को ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार

भारतीय मूल के तीन लोगों को इस साल ऑस्ट्रेलिया में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें यह सम्मान मेडिसीन व कम्युनिटी में उल्लेखनीय योगदान के लिए मिला है। सिडनी स्थित मेडिकल प्रैक्टिशनर, पुरुषोत्तम सावरिकर को 2017 के लिए ऑस्ट्रेलियाई पदक से सम्मानित किया गया।

क्या है

1. 26 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया दिवस के अवसर पर मेडिसीन और भारतीय समुदाय में उनके योगदान के लिए इस सम्मान की घोषणा की गयी।
2. सावरिकर ऑस्ट्रेलियन इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष थे और सामुदायिक रेडियो 'आकाशवाणी सिडनी' की भी स्थापना की थी।
3. पर्थ से माखन सिंह खांगुरे को न्यूरोरेडियालॉजी, शिक्षा और कई प्रोफेशनल मेडिकल असोसिएशन के लिए सम्मानित किया गया।
4. न्यूक्लियर मेडिसीन स्पेशलिस्ट और रिसर्चर, विजय कुमार को न्यूक्लियर मेडिसीन में मेडिकल रिसर्च और योगदान के लिए सम्मानित किया गया।
5. सिडनी तमिल संगम असोसिएशन की स्थापना करने वाली टीम के सदस्यों में से एक कुमार को 2007 और 2014 में ऑस्ट्रेलियन न्यूक्लियर साइंस और टेक्नोलॉजी आर्गेनाइजेशन अवार्ड मिल चुका है।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL) 7509975361, (PATNA) 7463950774, (DIBRUGARH) 7086708270, www.ksgindia.com

6. डारवेन के तेजिंदर पाल सिंह को भी ऑस्ट्रेलियन ऑफ द इयर के लोकल हीरो कैटेगरी अवार्ड से सम्मानित किया गया। सिंह ने समुदाय की बेहतरी में सराहनीय योगदान दिया है।
7. चार साल पुराने इनिशिएटिव 'फूड वैन' जिसके जरिए मुफ्त भोजन उपलब्ध कराया जाता है के लिए ही सिंह को नॉमिनेट किया गया था। इसके जरिए वे हर माह के अंतिम रविवार को उत्तरी डार्विन के गरीब और जरूरतमंदों को खाना मुहैया करा रहे थे।
8. इस साल ऑस्ट्रेलिया डे पर सम्मान के लिए 950 से अधिक ऑस्ट्रेलियाइ नागरिकां को नामित किया गया जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री जूलिया गिलार्ड विक्टोरियाई गर्वनर लिंडा डेसाउ, ऑर्गेनिक साइंटिस्ट एंड्रयू होम्स व पूर्व लिबरल एमपी डेविड केंप भा शामिल हैं।
9. इसके अलावा क्वींसलैंड के बायोमेडिकल वैज्ञानिक एलन मैके-सिम सम्मानित हुए और इन्हें ऑस्ट्रेलियन ऑफ द इयर का अवार्ड भी मिला।

हेल्थ सेक्टर में अफगानिस्तान और नेपाल से कम खर्च करता है भारत

भारत की ओर से स्वास्थ्य सेवा पर किए जाने वाले खर्च को कुछ ब्रिक्स एवं दक्षेस देशों से भी कम बताते हुए एक स्वास्थ्य संस्था ने केंद्र से कहा है कि वह आगामी बजट में परिवार नियोजन समेत स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश को बढ़ाए। स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन के लिए बजट आवंटन बढ़ाने को सबसे बड़ी प्राथमिकता बताते हुए पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि इस क्षेत्र में देश की ओर से कम खर्च किए जाने का परिणाम बढ़ती असमानताओं, स्वास्थ्य सेवाओं तक अपयार्प्त पहुंच और खराब गुणवत्ता के रूप में सामने आया है।

क्या है

1. पीएफआई की कार्यकारी निदेशक पूनम मुत्तरेजा ने कहा, भारत स्वास्थ्य सेवा पर अपनी जीडीपी का महज 1.3 प्रतिशत ही खर्च करता है। यह आंकड़ा ब्रिक्स देशों की तुलना में कहीं कम है। ब्राजील स्वास्थ्य सेवा पर लगभग 8.3 प्रतिशत, रूसी संघ 7.1 प्रतिशत और दक्षिण अफ्रीका लगभग 8.8 प्रतिशत खर्च करता है।
2. दक्षेस देशों में, अफगानिस्तान 8.2 प्रतिशत, मालदीव 13.7 प्रतिशत और नेपाल 5.8 प्रतिशत खर्च करता है। पीएफआई ने कहा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 2017 तक स्वास्थ्य पर जीडीपी का 2.5 प्रतिशत खर्च करने की सिफारिश करती है।
3. वर्ष 2015-16 और 2016-17 के बीच सरकार की ओर से स्वास्थ्य मंत्रालय को किए गए आवंटनों में 13 प्रतिशत की वद्धि हुई थी लेकिन मंत्रालय के बजट में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के हिस्से में गिरावट आई और यह 48 प्रतिशत हो गया।
4. बजट आवंटन की प्रवत्ति दशार्ती है कि परिवार नियोजन के प्रतिशत का अंश 2013-14 और 2016-17 में समान रहा है। यह स्वास्थ्य मंत्रालय के कुल बजट का दो प्रतिशत रहा है।
5. आर्थिक विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए स्वास्थ्य में निवेश अहम है। स्वास्थ्य सेवा की घरेलू मांग की आपूर्ति करने वाले स्वास्थ्य क्षेत्र में नए रोजगार देने की क्षमता है।
6. स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रशिक्षित श्रमशक्ति की भारी कमी है। निवेश बढ़ाने से स्वास्थ्य सेवाओं को कीमतें भी कम होंगी और इससे चार प्रतिशत की मध्यावधि मुद्रास्फीति के लक्ष्य को बनाए रखने में भी मदद मिलेगी।

फेडरर ने जीता साल का पहला ग्रैंड स्लैम

साल के पहले ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नमेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष एकल वर्ग में स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर ने अपन चिर प्रतिद्वंद्वी स्पेन के राफेल नडाल को हराकर अपने 18वें ग्रैंड स्लैम खिताब पर कब्जा कर लिया। फेडरर ने इस फाइनल मुकाबले को 6-4, 3-6, 6-1, 3-6 और 6-3 से अपने नाम किया। यह इन दोनों के बीच 9वां ग्रैंड स्लैम फाइनल मुकाबला था, जिसमें फेडरर तीसरी बार जीते हैं।

क्या है

1. फेडरर ने साल 5 साल बाद किसी ग्रैंड स्लैम का टाइटल अपने नाम किया है। इससे पहले उन्होंने साल 2012 में विम्बलडन जीता था। इसके बाद उनके करियर में ग्रैंड स्लैम टाइटल के लिए एक तरह का सूखा आ गया था, जिसे रविवार को मेलबर्न में उन्होंने खत्म किया। पुरुष एकल वर्ग में फेडरर पहले से सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब विजेता हैं।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL) 7509975361, (PATNA) 7463950774, (DIBRUGARH) 7086708270, www.ksgindia.com

2. यह फेडरर का 5वां ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब है। इससे पहले उन्होंने 2004, 2006, 2007 और 2010 में ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब अपने नाम किया था।
3. इन दोनों दिग्गज खिलाड़ियों के बीच हाने वाले इस फाइनल को ड्रीम फाइनल के तौर पर देखा जा रहा था और मेलबर्न के टेनिस मैदान की दर्शक दीर्घा दर्शकों से खचाखच भरी हुई थे। दोनों ही खिलाड़ियों के फैंस अपने-अपने चहेते खिलाड़ी का उत्साह बढ़ाते नजर आए।

न्यूयार्क की संघीय कोर्ट ने दिया डोनाल्डर ट्रंप को झटका

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कुछ देशों के नागरिकों को देश में न घुसने देने के फैसले का अमेरिका में ही जबरदस्त विरोध हो रहा है। न्यूयार्क के जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट के बाहर ट्रंप के आदेश के खिलाफ करीब दो हजार से अधिक लागों ने एकत्रित हुए और अपना विरोध जताया। हांलाकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि उनका आदेश मुसलमानों पर प्रतिबंध नहीं हैं। इसके अलावा एक संघीय अदालत ने भी राष्ट्रपति ट्रंप के अस्थायी आव्रजन प्रतिबंध के कुछ हिस्से को अवरूद्ध करते हुए अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे अमेरिकी हवाईअड्डों पर फंसे शरणार्थियों और अन्य यात्रियों को निर्वासित करना बंद करें। अमेरिकी सिविल लिबर्टीज यूनियन के वकीलों ने ट्रंप के शासकीय आदेश को रोकने के लिए सरकार पर मुकदमा किया था।

क्या है

1. गौरतलब है कि राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद अपने पहले ही आदेश में ईरान, इराक, लीबिया, सोमालिया, सुडान, सीरिया और यमन के नागरिकों के अमेरिका में घुसने पर प्रतिबंध लगा दिया था।
2. हस्ताक्षर करने के बाद ट्रंप ने कहा था कि अपने इस आदेश के जरिए चरमपंथी इस्लामी आतंकियों को अमेरिका से बाहर रखने के लिए कठोर जांच के नए नियम तय कर रहे हैं। उनका कहना था कि हम उन्हें यहां नहीं आने देना चाहते हैं। उनका कहना था कि 9/11 के बाद अमेरिका ने जो कदम उठाए, वे आतंकियों का देश में प्रवेश रोकने में कारगर नहीं रहे हैं।
3. इसमें कहा गया कि विदेशों में जन्मे बहुत से लोगों को 11 सितंबर 2001 के बाद से आतंकवाद संबंधी गतिविधियों में या तो दोषी करार दिया गया है या आरोपी बनाया गया है। इनमें वे विदेशी नागरिक भी शामिल हैं, जो अमेरिका में पर्यटक, छात्र या रोजगार वीजा लेकर आए थे या फिर अमेरिका में शरणार्थी पुनर्वास कार्यक्रम के तहत यहां आए थे। इसमें कहा गया कि कई देशों में युद्ध, भुखमरी, आपदा और असैन्य अशांति से बिगड़ती स्थिति के कारण यह आशंका बढ़ गई है कि आतंकी अमेरिका में दाखिल होने के लिए कोई भी माध्यम अपनाएंगे।

मिस यूनिवर्स 2016 का ताज फ्रांस के नाम

मिस यूनिवर्स साल 2016 में 85 सुंदरियों को पीछे छोड़ते हुए फ्रांस की आइरिस ने ये खिताब अपने काम किया। पूर्व मिस यूनिवर्स फिलीपींस की पिया अलोंजो ने उनके सिर पर ताज पहनाया। मिस यूनिवर्स की इस 65वीं प्रतियोगिता में 63 साल बाद फ्रांस की सुंदरी के नाम ये खिताब अपने नाम किया है।

क्या है

1. मिस यूनिवर्स का ताज अपने नाम करने वाली इरिस डेंटिस्ट्री की स्टूडेंट है। खाना पकाना उन्हें बेहद पसंद है। वहीं मिस यूनिवर्स की पहली रनरअप मिस हैती रहीं और दूसरी मिस कोलबिंया।
2. भारत का प्रतिनिधित्व कर रही रोशमिता हरिमूर्ति टॉप 13 में भी जगह बनाने में कामयाबी हासिल नहीं कर पाई।
3. इस बार की मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता इस बार भारत के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण था।
4. जहां भारत रोशमिता हरिमूर्ति ने भारत का प्रतिनिधित्व किया, तो सुष्मिता सेन इस शो की जज रहीं। वहीं भारतीय मूल की सिख गर्ल किरन जस्साल ने मलेशिया को प्रजेंट किया।

यह है दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ

दुनिया के सबसे महंगे पदार्थ की कीमत सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इसका नाम जानने के बाद आप ये सोच भी नहीं सकेंगे कि वाकई में इसकी कीमत इतनी ज्यादा होगी। आपमें से ज्यादातर लोग इसे सोना, चांदी या हीरा मान रहे होंगे। अगर ऐसा है तो आपको गलतफहमी में है। दुनिया की सबसे महंगा पदार्थ ऐंटिमैटर(प्रतिपदार्थ) है।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL) 7509975361, (PATNA) 7463950774, (DIBRUGARH) 7086708270, www.ksgindia.com

क्या है

1. प्रतिपदार्थ पदार्थ का एक ऐसा प्रकार है जो प्रतिकणों जैसे पाजिट्रॉन, प्रति-प्रोटॉन, प्रति-न्यूट्रांन मे बना होता है। ये प्रति-प्रोटॉन और प्रति-न्युट्रॉन प्रति क्वार्को मे बने होते हैं।
2. इसकी कीमत 1 ग्राम प्रतिपदार्थ को बेचकर दुनिया के 100 छोटे-छोटे देशों को खरीदा जा सकता है। 1 ग्राम प्रतिपदार्थ की कीमत 31 लाख 25 हजार करोड़ रुपये है। नासा के अनुसार,प्रतिपदार्थ धरती का सबसे महंगा मैटीरियल है। 1 मिलिग्राम प्रतिपदार्थ बनाने में 160 करोड़ रुपये तक लग जाते हैं।
3. जहां यह बनता है, वहां पर दुनिया की सबसे अच्छी सुरक्षा व्यवस्था मौजूद है। इतना ही नहीं नासा जैसे संस्थानों में भी इसे रखने के लिए एक मजबुत सुरक्षा घेरा है। कुछ खास लोगों के अलावा प्रतिपदार्थ तक कोई भी नहीं पहुंच सकता है।
4. प्रतिपदार्थ का इस्तेमाल अंतरिक्ष में दूसरे ग्रहों पर जाने वाले विमानों में ईधन की तरह किया जा सकता है।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, **(DELHI RN)** 9811293743, **(JAIPUR)** 8290800441, **(BHOPAL)** 7509975361, **(PATNA)** 7463950774, **(DIBRUGARH)** 7086708270, **www.ksgindia.com**